

[2023] 10 एस. सी. आर. 11

क.

ए. श्रीनिवासुलु

वी.

राज्य प्रतिनिधि। पुलिस निरीक्षक द्वारा (2010 की आपराधिक अपील संख्या 2417)

15 जून, 2023

[वी. रामसुब्रमणियन और पंकज मिहल, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860:एसएस।120 बी, 193,420,468 और 471-आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी-अभियोजन मामला कि अपीलकर्ता, पीएसयू के अधिकारियों और अन्य निजी व्यक्तियों ने अनुबंध देने के मामले में पीएसयू को धोखा देने के लिए एक आपराधिक साजिश में प्रवेश किया-एक कंपनी को सीमित/प्रतिबंधित निविदाओं का सहारा लेने के बाद दिया गया अनुबंध जिससे पीएसयू को गलत नुकसान हुआ-निविदा आमंत्रित करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया में कथित अवैधता-यू/एस में प्राथमिकी दर्ज की गई।120 बी आर/डब्ल्यू एसएस।193, 420, 468, 471 आर/डब्ल्यू एसएस।13 (2) और पी. सी. अधिनियम की 13 (1) (डी)-लोक सेवक-पीएसयू के अधिकारियों सहित अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ अंतिम रिपोर्ट-मुकदमे के दौरान दो अभियुक्तों की मृत्यु हो गई-विशेष न्यायाधीश ने एक को बरी कर दिया लेकिन चार को दोषी ठहराया-उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित-अपील पर अभिनिर्धारित किया:आई. पी. सी. और पी. सी. अधिनियम के तहत अपराधों के लिए अपीलार्थियों की दोषसिद्धि स्थापित और साबित नहीं हुई-इस प्रकार, अपीलार्थियों को विभिन्न अपराधों के लिए दोषी ठहराने वाले विशेष न्यायालय का निर्णय और उसी की पुष्टि करने वाले उच्च न्यायालय का निर्णय-भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 -एस. 13.

ग

डी.

ई.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:धारा 197 (1)-लोक सेवक का अभियोजन-पिछली मंजूरी-एक अनुचित और कम लाभ प्रदान करने की दृष्टि से पीएसयू के कार्यकारी निदेशक की आवश्यकता, चार फर्जी कंपनियों के नामों के साथ-साथ उस व्यक्ति के नाम को निर्देशित करके प्रतिबंधित निविदा के लिए चला गया जिसे अनुबंध दिया गया था-आरोप कि वह अपराध करने के लिए दूसरों के साथ आपराधिक साजिश में शामिल हो गया था-वह अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने से पांच साल पहले सेवानिवृत्त हो गया-मंजूरी पूर्व यू/एस।197 कार्यकारी निदेशक पर मुकदमा चलाने के लिए नहीं मांगा गया-की शुद्धता-आयोजित:अभियोजन पक्ष को एस के संदर्भ में पूर्व मंजूरी लेनी चाहिए थी।197(1) आई. पी. सी. के तहत अपराधों के लिए कार्यकारी निदेशक पर मुकदमा चलाने के लिए-मंजूरी की आवश्यकता न केवल आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किए गए कार्यों के लिए है, बल्कि आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए भी आवश्यक है और/या

च

जी.

एच.

11 ए.

12 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

ऐसे कर्तव्य या अधिकार के रंग या उससे अधिक के तहत किया गया कार्य-यदि सह-षड्यंत्रकारियों का वही कार्य वाणिज्यिक ज्ञान के दायरे में आता है, तो यह असंभव है कि कार्यकारी निदेशक का कार्य, आपराधिक साजिश के हिस्से के रूप में, उसके सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन से बाहर हो, ताकि उसे यू/एस सुरक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जा सके।**197(1)** - उसका कार्य, भले ही आरोप लगाया गया हो कि उसमें ईमानदारी की कमी है या किसी साजिश के अनुसरण में, उसके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में एक कार्य होगा, जिससे मामला एस के मापदंडों के भीतर आ जाएगा।**197(1)**.

एसएस।**306, 307** - अनुमोदक को क्षमा की निविदा-एस द्वारा निर्धारित प्रक्रिया।**306(4)(क)** का अनुपालन-तथ्यों के आधार पर, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जांच के चरण में माफी प्रदान की और अभियोजन पक्ष ने विशेष न्यायालय के समक्ष उसकी जांच की-याचिका है कि सरकारी गवाह, एस द्वारा कवर किए गए मामलों में।**306(1)**, दो बार जाँच की जानी चाहिए, एक बार अदालती गवाह के रूप में और फिर मुकदमे के समय अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में-आयोजित:जब विशेष न्यायालय संज्ञान लेने का विकल्प चुनता है, तो मजिस्ट्रेट के न्यायालय में गवाह के रूप में सरकारी गवाह से पूछताछ किए जाने का प्रश्न, जैसा कि एस द्वारा आवश्यक है।**306 (4)(क)** उत्पन्न नहीं होता है-किसी सरकारी गवाह से दो बार पूछताछ करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरोपी को प्रारंभिक चरण में भी उसके खिलाफ साक्ष्य के बारे में जागरूक किया जाए, ताकि वह मुकदमे के दौरान सरकारी गवाह से प्रभावी ढंग से जिरह कर सके, विरोधाभासों को सामने ला सके और उसे अविश्वसनीय साबित कर सके-तथ्यों पर, उद्देश्य पूरा हो गया-अपराध स्वीकार करने वाले मजिस्ट्रेट ने उससे पूछताछ की और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भी क्षमा प्रदान की-इस प्रकार, एस द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का कोई उल्लंघन नहीं हुआ।**306(4)(क)**-भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, **1988** -एस. 5.

ग

डी.

ई.

च

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना:**1**. दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, **1988** के तहत विभिन्न अपराधों के लिए अपीलार्थियों को दोषी ठहराने वाले विशेष न्यायालय के फैसले और इसकी पुष्टि करने वाले उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया गया है। [पैरा **139**] [72-एच; 73-ए] **2.1 ए-1** से **ए-4** तक, कंपनी के अधिकारी होने के नाते आई. पी. सी. की धारा **21** के तहत और पी. सी. अधिनियम की धारा **2 (सी) (iii)** के तहत उक्त अभिव्यक्ति की परिभाषा के भीतर 'लोक सेवक' थे। इसलिए, धारा ए दोनों के तहत पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है।

जी.

एच.

13

ए. श्रीनिवासुलु बनाम राज्य प्रतिनिधि. पुलिस निरीक्षक द्वारा ए.

197(1) आई. पी. सी. और पी. सी. अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के लिए **ए-1** से **ए-4** पर मुकदमा चलाने के लिए संहिता और पी. सी. अधिनियम की धारा **19 (1)** के तहत। [पैरा **29**] [35-एफ, जी]

2.2 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, **2018 (2018 का अधिनियम 16)** के तहत पी. सी. अधिनियम में संशोधन होने तक, धारा **19 (1) (ए)** के तहत पिछली मंजूरी की आवश्यकता केवल उस व्यक्ति तक सीमित थी जो नियोजित है। इसके विपरीत, धारा **197 (1)** ने "किसी भी व्यक्ति के संबंध में" और "किसी भी व्यक्ति के संबंध में जो" नियोजित "था, दोनों के संबंध में पूर्व मंजूरी की आवश्यकता को आवश्यक बना दिया। **2018** के अधिनियम **16** के तहत संशोधन द्वारा, पी. सी. अधिनियम की धारा **19 (1) (ए)** को उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया था ताकि पूर्व मंजूरी उस व्यक्ति के संबंध में भी आवश्यक हो जाए जो "अपराध करने के समय कार्यरत था"। [पैरा **30**] [35-एम; 36-ए-बी]

2.3 यह मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का अधिनियम 16) के लागू होने से पहले उठा था। इसलिए, जहां तक ए-1 का संबंध है, पीसी अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत कोई पूर्व मंजूरी आवश्यक नहीं थी, क्योंकि वह वर्ष 2002 में अंतिम रिपोर्ट दाखिल होने तक सेवानिवृत्त हो चुके थे। लेकिन ए-3 और ए-4 के संबंध में पीसी अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत पूर्व मंजूरी की आवश्यकता थी, क्योंकि वे विशेष न्यायालय के संज्ञान लेने के समय सेवा में थे। इसलिए एजेंसी ने मंजूरी मांगी, लेकिन जहां तक ए-3 और ए-4 का संबंध है, पीएसयू के प्रबंधन ने एक बार नहीं बल्कि दो बार मंजूरी देने से इनकार कर दिया। ए-3 और ए-4 द्वारा अपने नियोक्ता से प्राप्त परोपकार ए-1 के लिए भाग्य की विचित्रता या एक समय में पैदा होने (और परिणामस्वरूप एक विशेष समय पर सेवानिवृत्त होने) की दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के कारण उपलब्ध नहीं था। ए-3 और ए-4 के संबंध में अभियोजन के लिए मंजूरी देने से इनकार करने का ए-1 के अभियोजन पर सीधा असर नहीं पड़ सकता है। लेकिन यह निश्चित रूप से उस संदर्भ को प्रदान करेगा जिसमें आई. पी. सी. और पी. सी. अधिनियम दोनों के तहत अपराधों के लिए ए-1 की दोषिता का निर्धारण किया जाना है। [पारस 31,32,34] [36-सी-ई, एच; 37-ए]

डी.

ई.

च

जी.

2.4 मौजूदा नीति से पता चलता है कि ए-1 के पास कम से कम एक तर्कपूर्ण मामला था, उस निर्णय के बचाव में जो उसने प्रतिबंधित निविदा के लिए लिया था। एक बार जब यह स्पष्ट हो जाता है, तो उसका कार्य, भले ही आरोप लगाया गया हो

एच.

14 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

प्रामाणिक रूप से या किसी साजिश के अनुसरण में कमी होना, अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में एक कार्य होगा, जिससे मामला संहिता की धारा 197 (1) के मापदंडों के भीतर आता है। अतः अभियोजन पक्ष को पूर्व मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए थी। विशेष न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी इस पहलू पर अपना दिमाग नहीं लगाया। [पैरा 47] [41-जी-एच; 42-ए]

2.5 एफ. आई. आर. में वास्तव में केवल चार व्यक्तियों, अर्थात् पीडब्लू-16, ए-3, ए-4 और ए-5 को शामिल किया गया था। ए-1 को एफ. आई. आर. में शामिल नहीं किया गया था। वर्ष 1998 में पीडब्लू-16 द्वारा स्वीकारोक्ति बयान दिए जाने के बाद ही ए-1 को शामिल किया गया था। ए-1 के खिलाफ आरोप थे कि वह इन अपराधों को करने के लिए दूसरों के साथ आपराधिक साजिश में शामिल हो गया था। लेकिन पीएसयू के प्रबंधन ने दो बार ए-3 और ए-4 पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी देने से इनकार कर दिया, इस आधार पर कि लिए गए निर्णय कंपनी के वाणिज्यिक विवेक के दायरे में थे। यदि कंपनी के प्रबंधन के अनुसार, सह-षड्यंत्रकारियों का वही कार्य वाणिज्यिक ज्ञान के दायरे में आता है, तो यह अकल्पनीय है कि ए-1 का कार्य, आपराधिक साजिश के हिस्से के रूप में, उसके सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन से बाहर था, ताकि उसे संहिता की धारा 197 (1) के तहत संरक्षण के लिए अयोग्य घोषित किया जा सके। इसे ध्यान में रखते हुए अभियोजन पक्ष को आई. पी. सी. के तहत अपराधों के लिए ए-1 पर मुकदमा चलाने के लिए संहिता की धारा 197 (1) के संदर्भ में पूर्व मंजूरी लेनी चाहिए थी। [पारस 52,53] [43-सी-एफ]

ई.

3.1 संहिता की धारा**306** की शरीर रचना पर सावधानीपूर्वक नज़र डालने से पता चलता है कि यह वैकल्पिक या अतिरिक्त रूप से कई कदम प्रदान करता है। संहिता की धारा **307** उस न्यायालय को क्षमा करने का अधिकार देती है जिसके प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की जाती है। मामले की प्रतिबद्धता के बाद लेकिन निर्णय पारित होने से पहले किसी भी समय शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। [पारस **61,62**] [48-जी; 50-ए]

च

3.1 एस की उप-धारा **(1)** 5 पी. सी. अधिनियम विशेष न्यायाधीश को अभियुक्त को मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध किए बिना अपराधों का संज्ञान लेने का अधिकार देता है। इसमें यह भी कहा गया है कि अभियुक्त व्यक्तियों पर मुकदमा चलाते समय, विशेष न्यायाधीश मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों की सुनवाई के लिए संहिता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य है। पी. सी. अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश के पास अपराधों की सुनवाई करते समय सत्र न्यायाधीश के साथ-साथ ए.

जी.

एच.

15

ए. श्रीनिवासुलु बनाम राज्य प्रतिनिधि. पुलिस निरीक्षक द्वारा ए.

मजिस्ट्रेट का और यह कि ऐसा विशेष न्यायाधीश आरोप पत्र दाखिल करने से पहले और मुकदमा चलाने के लिए दोनों कार्यवाहियों का संचालन करता है। इसके विपरीत, पी. सी. अधिनियम की धारा **5 (2)** उस चरण के बारे में नहीं बताती है जिस पर एक विशेष न्यायाधीश द्वारा माफी दी जा सकती है। यह संभवतः धारा **5** की उप-धारा **(1)** के स्पष्ट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए है जो विशेष न्यायाधीश को स्वयं अभियुक्त को मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध किए बिना संज्ञान लेने का अधिकार देता है। लेकिन पी. सी. अधिनियम की धारा **5** की उप-धारा **(2)** का दूसरा भाग एक काल्पनिक कल्पना पैदा करता है कि विशेष न्यायाधीश द्वारा दी गई माफी को संहिता की धारा **307** के तहत दी गई माफी माना जाएगा। हालाँकि, यह काल्पनिक धारणा संहिता की धारा **308** की उप-धारा **(1)** से **(5)** के उद्देश्यों के लिए सीमित है। [पैरा **65**] [51-ए, बी]

ग

3.2 जब विशेष न्यायालय संज्ञान लेने का विकल्प चुनता है, तो धारा **376 (4) (ए)** द्वारा आवश्यक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में गवाह के रूप में सरकारी गवाह से पूछताछ करने का सवाल नहीं उठता है। [पैरा **76**] [57-डी]

डी.

3.3 सरकारी गवाह से दो बार पूछताछ करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरोपी को प्रारंभिक चरण में भी उसके खिलाफ साक्ष्य के बारे में जागरूक किया जाए, ताकि वह मुकदमे के दौरान सरकारी गवाह से प्रभावी ढंग से जिरह कर सके, विरोधाभासों को सामने ला सके और उसे अविश्वसनीय साबित कर सके। उक्त उद्देश्य तत्काल मामले में पूरा हो जाता है, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष सरकारी गवाह का स्वीकारोक्ति बयान आरोप पत्र के साथ संलग्न था। मुकदमे के दौरान सरकारी गवाह से पीडब्लू-**16** के रूप में पूछताछ की गई और स्वीकारोक्ति बयान की सामग्री पर उससे जिरह की गई। स्वीकारोक्ति दर्ज करने वाले मजिस्ट्रेट से पीडब्लू **17** के रूप में पूछताछ की गई और माफी देने वाले अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से पीडब्लू-**18** के रूप में पूछताछ की गई। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही, संहिता की धारा **376** के तहत याचिका और क्षमा की निविदा पर कार्यवाही को क्रमशः चिह्नित किया गया था। सभी अभियुक्तों को प्रक्रिया और विषय-वस्तु दोनों पर इन गवाहों से जिरह करने का अवसर दिया गया था। संहिता की धारा **376 (4) (ए)** द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था। [1. 1 निचली अदालत और उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दो बड़ी कंपनियों के नाम इसमें शामिल किए गए थे।

ई.

च

जी.

एच.

16 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

केवल अपनाई गई प्रक्रिया को विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए पी-26 चिट प्रदर्शित करें। लेकिन एल एंड टी कंपनी के प्रबंधक पीडब्लू-4 के बयान के माध्यम से यह रिकॉर्ड में था कि उन्हें पीएसयू से एक निविदा जांच प्राप्त हुई थी। यदि उन दोनों कंपनियों के नामों को शामिल करने का उद्देश्य एक विश्वास का मामला होना था, तो ए-1 ने पत्र भेजने का जोखिम नहीं उठाया होता और वह भी एलएंडटी जैसी कंपनी को। इसलिए, पीडब्लू-16 का साक्ष्य श्रेय के योग्य नहीं था; यह मानते हुए भी कि इसकी कुछ विश्वसनीयता है, उनके बयान कि "उन्होंने ए-5 को अनुबंध देने की सिफारिश ए-1 के हित के कारण नहीं की", ने पूरी इमारत को ध्वस्त कर दिया जिस पर अभियोजन पक्ष का मामला बनाया गया था; और यह कि ए-1 को इन अपराधों के करने से जोड़ने के लिए कोई अन्य सबूत नहीं था। [पैरा 102] [64-जी-एच; 65-ए, बी]

ग

4.2 दोनों अदालतों द्वारा धारा 120 बी के तहत अपराध का दोषी पाया जाने वाला एकमात्र व्यक्ति ए-1 था। इसलिए, एक तर्क दिया गया कि एक भी व्यक्ति को आपराधिक साजिश का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन इस तर्क को अदालतों ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि पीडब्लू-16 दूसरा व्यक्ति था जिसके साथ ए-1 ने साजिश रची थी। दूसरे शब्दों में, निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया तर्क यह था कि केवल ए-1 और पीडब्लू-16 साजिश का हिस्सा थे। इस तरह का तर्क मूल आरोप से एक बड़ी चढ़ाई थी कि ए-1 से ए-7 ने एक आपराधिक साजिश में प्रवेश किया, जिससे पीएसयू को गलत नुकसान हो और ए-5 से ए-7 को गलत लाभ दिया जा सके। एक बार जब ए-5 से ए-7 के खिलाफ धारा 120 बी का अपराध नहीं बनता है, तो अभियोजन की नींव ही अस्थिर हो जाती है। इसलिए, धारा 420, 468 के साथ पठित धारा 120 बी, धारा 468 के साथ पठित धारा 471 और आई. पी. सी. की धारा 193 और पी. सी. अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) के साथ पठित धारा 13 (2) के तहत अपराधों के लिए ए-1 की सजा कायम नहीं की जा सकती है। [पैरा 103] [65-सी-ई]

डी.

ई.

च

4.3 ए-1 को धारा 193 के तहत अपराध का दोषी पाया गया। धारा 193 केवल न्यायिक कार्यवाही के किसी भी चरण में दिए गए झूठे साक्ष्य या न्यायिक कार्यवाही के किसी भी चरण में उपयोग किए जाने के उद्देश्य से झूठे साक्ष्य के निर्माण पर लागू होती है। ए-1 के खिलाफ आरोप आई. पी. सी. की धारा 193 के तहत किसी भी स्पष्टीकरण से दूर से जुड़ा नहीं था। इसलिए, निचली अदालत और ए को दोषी ठहराने वाले उच्च न्यायालय का निर्णय

जी.

एच.

17

ए. श्रीनिवासुलु बनाम राज्य प्रतिनिधि. पुलिस निरीक्षक द्वारा ए.

उक्त अपराधों के लिए ए-1 और उसे अलग-अलग शर्तों के कारावास और अलग-अलग राशियों के जुर्माने की सजा को वापस लिया जा सकता है। [पैरा 104] [65-एफ-जी]

4.4 कोई भी न्यायालय आई. पी. सी. की धारा **193** के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, सिवाय उस न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय के लिखित शिकायत पर जिसके वह न्यायालय अधीनस्थ है। यह बार संहिता की धारा **195 (1) (बी) (आई)** में पाया जाता है। किसी भी अदालत या किसी भी अदालत द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा कभी भी कोई शिकायत नहीं की गई थी कि ए-1 या ए-3 या ए-4 ने आई. पी. सी. की धारा **193** के तहत दंडनीय अपराध किया है। लेकिन दुर्भाग्य से, निचली अदालत ने ए-1, ए-3 और ए-4 को बिना किसी समझदारी के धारा **193** के तहत अपराध का दोषी ठहराया और उच्च न्यायालय ने इसे बरकरार रखा है। [पैरा **108**] [66-ई, एफ]

ग

4.5 निचली अदालत और उच्च न्यायालय को इस तरह पढ़ना कि यह समिति, जिसमें ए-3, ए-4 और अनुमोदनकर्ता एक हिस्सा थे, वास्तव में एक निविदा समिति थी जिसकी बड़ी भूमिका थी, पूरी तरह से गलत धारणा है। वास्तव में, अभियोजन पक्ष को पी. डब्ल्यू.-16 नामक अनुमोदनकर्ता की गवाही के बल पर खड़ा होना या गिरना पड़ा। पीडब्ल्यू-16 द्वारा ए-3 और ए-4 को क्लिन चिट देने के दावे के बावजूद, निचली अदालत ने दोनों को एक जटिल तर्क पर दोषी पाया कि वे एक निविदा समिति का हिस्सा थे और "निविदा समिति की कार्यवाही में हर शब्द और हर विवरण उनके द्वारा पीएसयू को धोखा देने के उद्देश्य से लिखा गया था" और "यदि ए-3 और ए-4 निर्दोष थे तो उन्हें ठेकेदारों के बारे में पूछताछ करनी चाहिए थी और विवरण मांगना चाहिए था।" निचली अदालत द्वारा दिया गया और निचली अदालत द्वारा अनुमोदित और उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित ऐसा तर्क पूरी तरह से विकृत था। [पारस **110-112**] [64-D, E; 68-A, B]

डी.

ई.

च

4.6 ए-4 की निविदाकारों को चुनने में कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन निविदाकारों से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद ही इसमें प्रवेश किया। मान लीजिए, ए-4 पीडब्ल्यू-16 और ए-3 दोनों के अधीन था। सक्षम प्राधिकारी ने पीसी अधिनियम के तहत अपराधों के लिए ए-3 और ए-4 पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने ए-4 को सह-साजिशकर्ता नहीं पाया, यही कारण है कि उसे आई. पी. सी. की धारा **120-बी** के तहत अपराध का दोषी नहीं ठहराया गया। आई. पी. सी. की धारा **193** को पूरी तरह से संदर्भ से बाहर शामिल किया गया था। द.

जी.

एच.

18 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

निचली अदालत द्वारा ए-4 की दोषसिद्धि, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, पूरी तरह से अस्थिर है और इसे दरकिनार किया जा सकता है। [पारस **113-115**] [68-सी-ई]

4.7 अभियोजन पक्ष द्वारा जाँच किए गए चार में से तीन बैंक अधिकारियों ने यह दिखाने के लिए कि ए-7 ने चार फर्जी फर्मों की ओर से डिमांड ड्राफ्ट के लिए आवेदन किया था, ए-7 की पहचान उस व्यक्ति के रूप में नहीं की जिसने डिमांड ड्राफ्ट के लिए आवेदन किया था। उन्होंने प्रदर्शनी पी-66, पी-90 और पी-92 में ए-7 की लिखावट की भी पहचान नहीं की। अभियोजन पक्ष के पक्ष में कुछ कहने वाला एकमात्र व्यक्ति पीडब्ल्यू-32 था और यह प्रदर्शनी पी-76 के संबंध में था। [पैरा **122**] [69-एच; 70-ए] **4.8** अभियोजन पक्ष की ओर से यह स्थापित करने में भारी विफलता थी कि प्रदर्शनी पी-66, पी-76, पी-90 और पी-92 ए-7 के हस्तलेखन/हस्ताक्षर में थे। यह अभियोजन पक्ष द्वारा पी. डब्ल्यू.-22, पी. डब्ल्यू.-32, पी. डब्ल्यू.-40 और पी. डब्ल्यू.-41 के रूप में बैंक अधिकारियों और पी. डब्ल्यू.-30 के रूप में हस्तलेखन विशेषज्ञ की जांच के बावजूद है। [पैरा **128**] [71-ए]

डी.

4.9 दुर्भाग्य से, निचली अदालत ने एक बहुत ही जिज्ञासु तर्क अपनाया कि चूंकि वह सहयोगी संस्था के खाते में भेजे गए धन का लाभार्थी था, इसलिए उसे भागीदारी और जानकारी होनी चाहिए कि डिमांड ड्राफ्ट पीएसयू को धोखा देने के लिए खरीदे गए थे। इस तरह का तर्क इस तथ्य को देखते हुए पूरी तरह से अस्वीकार्य है कि ए-7 पर जालसाजी का आरोप लगाया गया था और उस पर यू/एस का आरोप लगाया गया था। **468** आई. पी. सी., मांग मसौदे के लिए इन समान अनुप्रयोगों के संबंध में। इसलिए, अभियोजन पक्ष के लिए जालसाजी साबित करना और यह भी दिखाना आवश्यक था कि इस तरह की जालसाजी का उद्देश्य धोखाधड़ी था। दोनों अनुपस्थित थे। सौभाग्य से उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के तर्क में कमी को महसूस किया। लेकिन ए-7 को किसी तरह दोषी ठहराने की अत्यधिक चिंता में, उच्च न्यायालय ने एक बहुत ही विचित्र मार्ग अपनाया, जिसका नाम है विवादित हस्ताक्षरों के साथ स्वीकार किए गए हस्ताक्षरों/हस्तलेखन की तुलना करने का कार्य करना। **73** साक्ष्य अधिनियम। [पारस **129,130**] [71-बी-ई]

ई.

च

4.10 उच्च न्यायालय के समक्ष कोई हस्ताक्षर या लेखन उपलब्ध नहीं था, जिसे न्यायालय की संतुष्टि के लिए स्वीकार या साबित किया गया था। उच्च न्यायालय ने ए-7 को तुलना को सक्षम करने के उद्देश्य से कोई शब्द या आंकड़े लिखने का भी निर्देश नहीं दिया। प्रक्रिया का पालन किए बिना ए

जी.

एच.

19

ए. श्रीनिवासुलु बनाम राज्य प्रतिनिधि. पुलिस निरीक्षक द्वारा ए.

धारा **73** में निर्धारित, उच्च न्यायालय ने एक नई प्रक्रिया का आविष्कार किया, ताकि निचली अदालत द्वारा गलत तर्क के माध्यम से दी गई दोषसिद्धि को बरकरार रखा जा सके। यहां तक कि संहिता की धारा **313** के तहत पूछताछ में भी ए-7 से कोई विशिष्ट प्रश्न नहीं पूछा गया था कि क्या प्रदर्शनी पी-66, पी-76, पी-90, पी-92 और पी-75 उनकी लिखावट में थे और क्या उनमें उनके हस्ताक्षर थे। इसलिए, प्रदर्शनी पी-75 में जो शामिल था, उस पर हस्ताक्षर भी स्वीकार नहीं किए गए थे। स्वीकार किए गए हस्ताक्षरों की स्वीकृति या प्रमाण के अभाव में, उच्च न्यायालय साक्ष्य अधिनियम की धारा **73** का सहारा नहीं ले सकता था। इसे ध्यान में रखते हुए, निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष, जैसे कि ए-7 ने फर्जी फर्मों के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट जारी करने के लिए आवेदन करके जालसाजी और धोखाधड़ी की है, पूरी तरह से अस्थिर है। [पारस **132,135-137**] [71-F, G; 72-C-E]

ग

4.11 ए-7 के खिलाफ इंगित एकमात्र जुड़ाव लिंक उस फर्म के खाते में रु. **1,52,50,000/-** की कुल सीमा तक धन का हस्तांतरण था जिसमें वह एक भागीदार था। यह अपने आप में कोई अपराध नहीं होगा। इसलिए, यह आरोप भी विफल होना चाहिए कि ए-7 ने अन्य अभियुक्तों को अपराध करने के लिए उकसाया। यह विशेष रूप से तब होता है जब ए-5, जिसकी स्वामित्व वाली संस्था ने अनुबंध प्राप्त किया था, ने न केवल अनुबंध खो दिया, बल्कि पीएसयू द्वारा बैंक गारंटी को भी लागू करने की अनुमति दी और इसके अलावा, रु. **2. 60** करोड़ अभी भी पीएसयू के पास हैं। इसलिए ए-7 को दी गई दोषसिद्धि और सजा को कायम नहीं रखा जा सकता है। [पैरा **138**] [72-एफ-जी]

डी.

ई.

सुरेश चंद्र बहरी बनाम बिहार राज्य **1995** सप्लीमेंट (1)

एससीसी **80:[1994] 1** पूरक।एससीआर **483**-प्रतिष्ठित।

च

बंगारु लक्ष्मण बनाम राज्य (सीबीआई के माध्यम से) **(2012) 1 एससीसी 500:[2011] 13 एस. सी. आर. 268;** सी. बी. आई. बनाम वी. अरुल के माध्यम से राज्य

कुमार (2016) 11 एससीसी 733:[2016] 2 एससीआर 486; सरदार

इकबाल सिंह बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) **(1977) 4**

एससीसी 536:[1978] 2 एस. सी. आर. 174; याकूब अब्दुल रजाक

जी.

मेमन बनाम महाराष्ट्र राज्य **(2013) 13 एससीसी 1:[2013] 15 एससीआर 1;** सरवन सिंह बनाम पंजाब राज्य **1957 एससीआर 953;** रविंदर सिंह बनाम हरियाणा राज्य

(1975) 3 एससीसी 742:[1975] 3 एस. सी. आर. 453-पर निर्भर।

एच.

20 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

माताजोग डोबे बनाम एच. सी. भारी **[1955] 2 एस. सी. आर 925;** डॉ. होरी राम सिंह बनाम। क्राउन **1939 एस. सी. सी. ऑनलाइन एफ. सी. 2;** कुमार राघवेंद्र सिंह के माध्यम से उड़ीसा राज्य

बनाम गणेश चंद्र यहूदी (2004) 8 एस. सी. सी. 40:[2004] 3

एस. सी. आर. **504;** के. कलिमुथु बनाम डी. एस. पी. द्वारा राज्य **(2005) 4 एस. सी. सी. 512:[2005] 3 एस. सी. आर. 1;** राकेश कुमार मिश्रा बनाम राज्य

बिहार (2006) 1 एस. सी. सी. 557:[2006] 1 एससीआर 124;

देविंदर सिंह बनाम सी. बी. आई. के माध्यम से पंजाब राज्य **(2016)**

12 एससीसी 87:[2016] 6 एस. सी. आर. 295; डी. देवराज बनाम. ओवैस साबिर हुसैन (2020) 7 एस. सी. सी. 695:[2020] 6 एससीआर 453;

प्रकाश सिंह बादल बनाम पंजाब राज्य **(2007) 1 एससीसी**

ग

1 :[2006] 10 पूरक।एससीआर 197; हर्षद एस. मेहता बनाम महाराष्ट्र राज्य (2001) 8 एससीसी 257:[2001] 2

पूरक।एस. सी. आर. **577;** केंद्रीय जांच ब्यूरो, चेन्नई बनाम वी. अरुल कुमार **(2016) 11 एस. सी. सी. 733** के माध्यम से राज्य:**[2016] 2 एस. सी. आर. 486;** ए. देवेंद्रन बनाम स्टेट ऑफ

टी. एन. (1997) 11 एस. सी. सी 720:[1997] 4 पूरक।एससीआर 591; पी. सी. मिश्रा बनाम राज्य (सीबीआई) (2014) 14 एससीसी 629:[2014]

डी.

4 एस. सी. आर. 183; एम. शम्सुद्दीन बनाम केरल राज्य **(1995)**

3 एससीसी 351:[1995] 2 एस. सी. आर. 900-संदर्भित।निर्णीत विधि संदर्भ

ई.

(1955) 2 एससीआर 925

संदर्भित

पैरा **38**

[2004] 3 एससीआर 504

संदर्भित किया गया है

पैरा **39**

[2005] 3 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा **40**

[2006] 1 एससीआर 124

संदर्भित किया गया है

पैरा **40**

च

संदर्भित किया गया है

पैरा **41**

[2016] 6 एससीआर 295

[2020] 6 एससीआर 453

पर भरोसा किया

पैरा **42,43 [2006] 10 पूरक।एस. सी. आर. 197 पैरा 48 [2001] 2 सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस. सी. आर. 577 पैरा 57 [2014] 4 एस. सी. आर. 183 में संदर्भित है।**

जी.

संदर्भित किया गया है

पैरा **57,74**

[2016] 2 एससीआर 486

पर भरोसा किया

पैरा **74**

पैरा **63**

[2011] 13 एससीआर 268

पर भरोसा किया

[1997] 4 पूरक।एस. सी. आर. 591 पैरा 67 ए. में निर्दिष्ट है।

एच.

21

ए. श्रीनिवासुलु बनाम राज्य प्रतिनिधि. पुलिस निरीक्षक द्वारा ए.

[1994] 1 पूरक।एस. सी. आर. 483 विशिष्ट पैरा 72 [1978] 2 एस. सी. आर. 174

पर भरोसा किया

पैरा **76**

[2013] 15 एससीआर 1

पर भरोसा किया

पैरा **76**

[1957] एससीआर 953

पर भरोसा किया

पैरा **83**

[1975] 3 एससीआर 453

पर भरोसा किया

पैरा **83**

[1995] 2 एससीआर 900

संदर्भित किया गया है

पैरा **84**

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार : 2010 की आपराधिक अपील संख्या 2417।

2006 के सी. आर. एल. ए. सं. 437 में मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 17.09.2010 के निर्णय और आदेश से।

ग

सह

आपराधिक अपील सं. 2011 की 16 और 2010 की 2444।

नागमुथु, श्रीमती वी. मोहना, हुजेफा ए. अहमदी, वरिष्ठ अधिवक्ता।, विजय कुमार, बी. रघुनाथ, एन. श्रीधर, श्रीमती एन. सी. कविता, कार्तिक सुब्रमण्यम, सुश्री रंजीता रोहतगी, कौशिक मिश्रा, सुश्री रश्मि सिंह, सुश्री समतेन डोमा लाचुंगपा, निशांत शर्मा, राकेश के. शर्मा, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

डी.

संजय जैन, ए. एस. जी., ए. के. कौल, सुश्री सृष्टि मिश्रा, पद्मेश मिश्रा, सुश्री श्रद्धा देशमुख, माधव सिंहल, अरविंद कुमार शर्मा, अधिवक्ता/उत्तरदाता के लिए।

ई.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

वी. रामसुब्रमण्यन, जे.

च

1. ये तीन आपराधिक अपीलें मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ द्वारा पारित एक सामान्य निर्णय से उत्पन्न होती हैं जो भारतीय दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत विभिन्न अपराधों के लिए अपीलार्थियों की दोषसिद्धि की पुष्टि करता है।

2. हमने श्री हुजेफा ए. अहमदी, श्री एस. नागमुथु, श्रीमती वी. मोहना, विद्वान वरिष्ठ वकील और श्री एस. आर. रघुनाथन, विद्वान वकील, अपीलार्थियों की ओर से पेश हुए और श्री संजय जैन, विद्वान ए. एस. जी, केंद्रीय जांच ब्यूरो के विद्वान वकील श्री पद्मेश मिश्रा की सहायता से सुना है।

जी.

1 संक्षेप में, "आई. पी. सी". 2 संक्षेप में, "पी. सी. अधिनियम"

एच.

22

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

3. उपरोक्त अपीलों की ओर ले जाने वाले संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं: (i) सात व्यक्तियों, जिनमें से चार बी. एच. ई. एल., त्रिची (एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम) के अधिकारी थे, और शेष तीन निजी उद्यम में लगे हुए थे, पर पुलिस निरीक्षक, एस. पी. ई./सी. बी. आई./ए. सी. बी., चेन्नई द्वारा एक अंतिम रिपोर्ट दिनांक 16.07.2002 के माध्यम से धारा 120 बी के साथ धारा 420, 468, धारा 471 के साथ धारा 468 और आई. पी. सी. की धारा 193 और पी. सी. अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) के साथ धारा 13 (2) के तहत कथित अपराधों के लिए आरोप लगाया गया। सी. बी. आई. मामलों के लिए प्रधान विशेष न्यायाधीश, मदुरै द्वारा 2002 के सी. सी. संख्या 9 में संज्ञान लिया गया था। मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, दो अभियुक्तों, ए-5 और ए-6 की मृत्यु हो गई।

ग

(ii) 08.09.2006 के एक फैसले से, विशेष अदालत ने ए-2 को बरी कर दिया और ए-1, ए-3, ए-4 और ए-7 को विभिन्न अपराधों के लिए दोषी ठहराया। इन चार दोषी व्यक्तियों ने मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ की फाइल पर 2006 की आपराधिक अपील (एम. डी.) Nos. 437, 445 और 469 में तीन अपील दायर की।

डी.

(iii) दिनांक 17.09.2010 के एक सामान्य निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने अपीलों को खारिज कर दिया, जिससे ए-1, ए-3, ए-4 और ए-7 को चार आपराधिक अपीलों, अर्थात् 2010 की अपील Nos. 2417, 2443 और 2444 और 2011 की 16 के साथ आने के लिए मजबूर होना पड़ा।

ई.

च

4. चूँकि सभी अपीलार्थियों के खिलाफ बनाए गए आरोप समान नहीं थे और चूँकि इसमें सभी अपीलार्थियों को उनके खिलाफ लगाए गए सभी अपराधों के लिए समान रूप से दोषी नहीं ठहराया गया था, इसलिए हम नीचे एक सारणीबद्ध रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिन अपराधों के लिए उनमें से प्रत्येक के खिलाफ आरोप बनाए गए थे, जिन अपराधों के लिए उनमें से प्रत्येक को दोषी ठहराया गया था और जिन अपराधों के लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया था।

जी.

एच.

23

ए. श्रीनिवासुलु बनाम राज्य प्रतिनिधि. पुलिस निरीक्षक द्वारा [वी. रामसुब्रमणियन, जे.] ए.

क.

ग

डी.

45.

च

जी.

एच.

24 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

ए7	N.Raghunath	धारा 120 बी को	आई. पी. सी. की	आई. पी. सी. की
----	-------------	----------------	----------------	----------------

	, ए-5 का भाई और ए-6 का बेटा	420,468,471 के साथ 468 और 193 आई. पी. सी. के साथ पढ़ा जाता है और पी. सी. अधिनियम की धारा 13 (2) को 13 (1) (डी) के साथ पढ़ा जाता है। इसके अलावा, उन पर आईपीसी की धारा 109 के तहत भी आरोप लगाया गया था।	धारा 471 को 468 और 109 के साथ पढ़ा जाता है और पी. सी. अधिनियम की धारा 13 (2) को 13 (1) (ई) के साथ पढ़ा जाता है।	धारा 420 और 193 के साथ पठित धारा 120 बी के तहत अपराधों का दोषी नहीं पाया गया।
--	--------------------------------	---	---	--

5. आसान मूल्यांकन के लिए, विशेष न्यायालय द्वारा प्रत्येक अभियुक्त को अपराध के आधार पर दिए गए और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए दंड को फिर से एक सारणीबद्ध कॉलम में प्रस्तुत किया गया है:

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

25

ए. श्रीनिवासुलु बनाम राज्य प्रतिनिधि. पुलिस निरीक्षक द्वारा [वी. रामसुब्रमणियन, जे.] ए.

क.

6. अपीलार्थियों के अभियोजन और उनके अंतिम दोषसिद्धि की ओर ले जाने वाले पृष्ठभूमि तथ्यों का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है:- (i) 1991-92 अवधि के दौरान, तमिलनाडु जल आपूर्ति और जल निकासी बोर्ड ने तमिलनाडु के रामनाड जिले में सूखा-प्रवण क्षेत्रों में पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के लिए "आरओडी संयंत्र" (रिवर्स ऑस्मोसिस डिसेलिनेशन संयंत्र) स्थापित करने का निर्णय लिया। उन्होंने बी. एच. ई. एल., तिरुचिरापल्ली को काम सौंपा। (ii) सीमित/प्रतिबंधित निविदाओं का सहारा लेने के बाद, बी. एच. ई. एल. ने एक एंटोमा हाइड्रो सिस्टम को अनुबंध प्रदान किया।

(iii) उक्त कंपनी को 06.07.1994 पर एक आशय पत्र जारी किया गया था और 02.08.1994 पर रु। मेसर्स एंटोमा हाइड्रो सिस्टम्स को 4.32 करोड़ रुपये जारी किए गए।

ग

(iv) लेकिन बाद में, अनुबंध को 04.10.1996 पर भी रद्द कर दिया गया था; ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी को 27.09.1996 पर लागू किया गया था; और रुपये. 4,84,13,581/- का भुगतान भेल द्वारा किया गया था।

डी.

(v) इसके बाद, 31.01.1997 पर, सी. बी. आई. ने अपराध सं. चार व्यक्तियों के खिलाफ 97 का आर. सी. 8 (ए), जिनमें से तीन बी. एच. ई. एल. के अधिकारी थे और चौथा ठेकेदार था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि बी. एच. ई. एल. के तीन अधिकारियों और ठेकेदार ने बी. एच. ई. एल. को धोखा देने के लिए आपराधिक साजिश रची और बी. एच. ई. एल. को 5 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया। उपरोक्त संस्था को अनुबंध प्रदान करके 4 करोड़ 32 लाख रुपये। एफ. आई. आर. धारा 120 बी के साथ 420, आई. पी. सी. की धारा 420 और पी. सी. अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) के साथ धारा 13 (2) के तहत अपराधों के लिए थी।

ई.

च

(vi) नवंबर 1998 में, पहली बार एफ. आई. आर. में नामित व्यक्ति, डी. जी. एम., राव को गिरफ्तार किया गया था और स्वयं सी. बी. आई. द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया था। इसके बाद, उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत चेन्नई के XVIII मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष स्वीकारोक्ति दी। इस तरह के कबूलनामे के बाद, सी. बी. आई. ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मदुरै के समक्ष संहिता की धारा 206 के तहत 2000 की आपराधिक विविध याचिका No.562 में एक आवेदन दायर किया।

जी.

एच.

26

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

K.Bhaskar राव को माफी देने के लिए। याचिका अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मदुरै को सौंपी गई, जिन्होंने भास्कर राव को माफी देने के लिए 18.07.2000 दिनांकित आदेश पारित किया।

(vii) इसके बाद, सी. बी. आई. ने बी. एच. ई. एल. के अध्यक्ष से पी. सी. अधिनियम के तहत अपराधों के लिए एफ. आई. आर. में नामित अन्य दो अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने का अनुरोध किया। लेकिन दिनांक 1 के पत्र द्वारा, बी. एच. ई. एल. के अध्यक्ष ने पी. सी. अधिनियम के तहत अपराधों के लिए एफ. आई. आर. में नामित उन दो अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

(viii) जाँच पूरी होने के बाद, सी. बी. आई. ने सात अभियुक्तों के खिलाफ आई. डी. 1 पर अंतिम रिपोर्ट दायर की, (i) ए. श्रीनिवासुलु, पूर्व कार्यकारी निदेशक, बी. एच. ई. एल.; (ii) आर. कृष्ण राव, सेवानिवृत्त महाप्रबंधक, बी. एच. ई. एल.; (iii) आर. त्यागराजन, सहायक महाप्रबंधक (वित्त), बी. एच. ई. एल.; (iv) के. चंद्रशेखरन, उप महाप्रबंधक, बी. एच. ई. एल.; (v) मोहन रामनाथ प्रोपराइटर, एंटोमा हाइड्रो सिस्टम्स; (vi) एन. आर. एन. अय्यर; और (vii) एन. रघुनाथ। अंतिम रिपोर्ट सीधे सी. बी. आई. मामलों के लिए प्रधान विशेष अदालत, मदुरै के समक्ष दायर की गई थी।

ग

डी.

(ix) अंतिम रिपोर्ट में, अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया:- ए-1 से ए-7 तक धारा 120 बी के साथ धारा 420, 468, धारा 471 के साथ धारा 468, आई. पी. सी. की धारा 193 और पी. सी. अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) के साथ धारा 13 (2) के तहत अपराधों के लिए।

ई.

पी. सी. अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (डी) के साथ पठित धारा 13 (2) और आई. पी. सी. की धारा 109 के साथ पठित धारा 420, 468, धारा 471 के साथ पठित धारा 468 और आई. पी. सी. की धारा 193 के तहत अपराधों के लिए ए-1 और ए-2।

च

ए-3 और ए-4 धारा 109 आई. पी. सी. के तहत अपराधों के लिए धारा 420, 468, धारा 471 के साथ धारा 468 और धारा 193 आई. पी. सी. के साथ पढ़ा जाता है।

जी.

ए-5, ए-6 और ए-7 धारा 420, 468, धारा 471 के साथ धारा 468, आई. पी. सी. की धारा 193 और आई. पी. सी. की धारा 109 के साथ पी. सी. अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) के तहत अपराधों के लिए।

एच.

27

ए. श्रीनिवासुलु बनाम राज्य प्रतिनिधि. पुलिस निरीक्षक द्वारा [वी. रामसुब्रमणियन, जे.] ए.

क.

(x) विशेष न्यायाधीश ने **04.07.2003** पर आरोप तय किए।(xi) अभियोजन पक्ष ने **44** गवाहों से पूछताछ की और **94** दस्तावेजों को चिह्नित किया।ए-5 और ए-6 की मुकदमे के लंबित रहने तक मृत्यु हो गई और इसलिए उनके खिलाफ आरोप समाप्त कर दिए गए।

(xii) दिनांक **08.09.2006** के एक निर्णय द्वारा, सी. बी. आई. मामलों के लिए प्रधान विशेष न्यायाधीश ने ए-2 को बरी कर दिया, लेकिन ए-1, ए-3, ए-4 और ए-7 को उपरोक्त पैराग्राफ 4 के तहत तालिका के कॉलम संख्या 4 में बताए गए विभिन्न अपराधों के लिए दोषी ठहराया।

(xiii) दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देते हुए, ए-1 ने मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ की फाइल पर 2006 की आपराधिक अपील में एक अलग अपील दायर की।ए-3 और ए-4 ने एक साथ मिलकर 2006 की आपराधिक अपील No.469 में एक आम अपील दायर की।ए-7 ने 2006 की आपराधिक अपील No.445 में एक अलग अपील दायर की।

ग

(xiv) मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने दिनांक **1** के एक निर्णय द्वारा तीनों अपीलों को खारिज कर दिया।

डी.

(xv) इसलिए, ए-1, ए-3, ए-4 और ए-7 ने 2010 की आपराधिक अपील Nos.2417,2443 और 2444 और 2011 की 16 में क्रमशः इस न्यायालय के समक्ष चार स्वतंत्र अपीलें दायर कीं।लेकिन ए-3,2010 की आपराधिक अपील में अपीलार्थी की अपील लंबित रहने तक मृत्यु हो गई और इसलिए उनकी अपील को निरस्त कर दिया गया।इसलिए, अब हमारे पास ए-1, ए-4 और ए-7 द्वारा दायर तीन अपीलें बची हैं जो दोषसिद्धि के समवर्ती निर्णयों से उत्पन्न होती हैं।

ई.

7. संक्षेप में, अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि ए-1 से ए-7 ने विलवणीकरण संयंत्रों के निर्माण के लिए अनुबंध देने के मामले में भेल को धोखा देने के लिए आपराधिक साजिश रची।उक्त साजिश के अनुसरण में, बी. एच. ई. एल. के तत्कालीन कार्यकारी निदेशक ए-1 ने डी. जी. एम. (जो स्वीकृत हुए) भास्कर राव को सीमित निविदाएं आमंत्रित करने से पहले संभावित निविदाकारों की पूर्व-योग्यता की निविदा प्रक्रिया का पालन किए बिना सीमित/प्रतिबंधित निविदाओं के लिए जाने का निर्देश दिया।अभियोजन पक्ष के अनुसार, ए-1 ने सीमित निविदाएं आमंत्रित करने के लिए मेसर्स एंटोमा हाइड्रो सिस्टम्स के नाम के साथ-साथ उसके मालिक ए-5 द्वारा प्रतिनिधित्व की गई चार फर्जी फर्मों के नाम निर्धारित किए।ए-1 के आदेशों के अनुसार, अनुमोदनकर्ता ने दो कंपनियों के नामों के साथ पांच फर्मी (चार फर्जी फर्मों सहित) के नामों का सुझाव देते हुए एक प्रस्ताव रखा, जो समान रूप से काम नहीं कर रही थीं।इसके बाद, ए-2,

च

जी.

एच.

28

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

यह अच्छी तरह से जानते हुए कि फर्म फर्जी थे और न तो पूर्व-योग्य थे और न ही ठेकेदारों की अनुमोदित सूची से चुने गए थे, अनुमोदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत नोट को संसाधित किया और इसे ए-1 को भेजा।जब निविदा पूछताछ की गई, तो ए-5 ने न केवल मेसर्स एंटोमा हाइड्रो सिस्टम्स के नाम पर बल्कि चार फर्जी फर्मों की ओर से भी इसका जवाब दिया।ए-5 के भाई ए-7 ने इंडियन बैंक, रोयापेट्टा शाखा, भारतीय स्टेट बैंक, वेलाचेरी शाखा, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, टी. नगर शाखा और बैंक ऑफ मदुरा, माउंट

रोड शाखा में नकदी भेजकर और डिमांड ड्राफ्ट आवेदन भरकर और फर्जी फर्मों के नाम पर हस्ताक्षर करके फर्जी फर्मों के नाम पर प्रत्येक के लिए Rs.20,000/- का डिमांड ड्राफ्ट प्राप्त किया। इसके बाद, अनुमोदनकर्ता, ए-3 और ए-4 वाली निविदा समिति ने इन सभी फर्मों के नामों को संसाधित किया और मेसर्स एंटोमा हाइड्रो सिस्टम्स को अनुबंध देने की सिफारिश की, जिसमें उनकी सिफारिश करने के लिए गलत औचित्य दिया गया, हालांकि उक्त फर्म के पास आवश्यक विशेषज्ञ या तकनीकी विशेषज्ञता नहीं थी। समिति ने ए-5 को आर्थिक लाभ पहुँचाने के लिए मौजूदा प्रथा का उल्लंघन करते हुए ब्याज मुक्त जुटान अग्रिम की मंजूरी देने की भी सिफारिश की। तदनुसार, रुपये का ब्याज मुक्त जुटान अग्रिम। ए-5 की फर्म को 4.32 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। यह राशि इंडियन बैंक में फर्म के खाते में जमा की गई थी। उक्त खाते से रु. 52 करोड़ रुपये ए-5 की सहायक कंपनी को दिए गए, जिसमें ए-5, उसके पिता (ए-6) और उसका भाई (ए-7) भागीदार थे। इस तरह की कार्रवाई से ए-5 से ए-7 ने बी. एच. ई. एल. से गलत लाभ प्राप्त किया। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि इन कार्रवाइयों से ए-1 से ए-7 ने उनके खिलाफ लगाए गए अपराधों को अंजाम दिया। 8. जैसा कि ऊपर पैरा 6 में कहा गया है, अभियोजन पक्ष ने 44 गवाहों से पूछताछ की, जिसमें अनुमोदनकर्ता भी शामिल था, जिससे पीडब्लू-16 के रूप में पूछताछ की गई थी। अभियोजन पक्ष के पक्ष में 94 दस्तावेजों को प्रदर्शन के रूप में चिह्नित किया गया था। बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह से पूछताछ की गई क्योंकि डी. डब्ल्यू.-1 और 6 दस्तावेजों को प्रदर्शन एक्स के रूप में चिह्नित किया गया था। डी-1 से डी-6।

ग

डी.

ई.

च

9. आई. डी. 1 दिनांकित अपने निर्णय में, विशेष न्यायालय ने पैराग्राफ 1 से 60 तक के आरोपों, साक्ष्य और प्रतिद्वंद्वी दलीलों को रिकॉर्ड में लाया। न्यायालय द्वारा वास्तविक चर्चा और विश्लेषण अनुच्छेद 61 से शुरू हुआ।

जी.

10. शुरुआत में, विशेष अदालत ने अभियुक्त के इस तर्क पर विचार किया कि बी. एच. ई. एल. को कोई गलत नुकसान नहीं हुआ है और इसलिए आई. पी. सी. की धारा 420 के तहत आरोप नहीं है। लेकिन अभियुक्त के इस तर्क को निचली अदालत ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि रुपये का संपूर्ण ब्याज मुक्त जुटान अग्रिम। 4. 42 करोड़ ए

एच.

29

ए. श्रीनिवासुलु बनाम राज्य प्रतिनिधि. पुलिस निरीक्षक द्वारा [वी. रामसुब्रमणियन, जे.] ए.

भारतीय बैंक के साथ मेसर्स एंटोमा हाइड्रो सिस्टम्स के खाते में जमा किया गया था और इसमें से 10,000 रुपये की राशि मेसर्स इंसेक्टिसाइड्स एंड एलाइड केमिकल्स नाम की एक फर्म को हस्तांतरित की गई थी, जिसमें ए-5 से ए-7 भागीदार थे। इसलिए, विशेष अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि जिस तारीख को धन का हस्तांतरण हुआ था, उस तारीख को बी. एच. ई. एल. को सीधा गलत मौद्रिक नुकसान हुआ था और ए-5 से ए-7 को सीधा गलत मौद्रिक लाभ हुआ था। विशेष अदालत ने यह भी कहा कि मेसर्स एंटोमा हाइड्रो सिस्टम्स के साथ अनुबंध की समाप्ति के बाद, बी. एच. ई. एल. ने अनुबंध को कई भागों में विभाजित किया और विभिन्न व्यक्तियों को अनुबंध दिए और इसलिए, ऐसे प्रत्येक ठेकेदार को दिया गया धन बी. एच. ई. एल. को गलत नुकसान था। हालांकि विशेष अदालत ने यह भी पाया कि बी. एच. ई. एल. ने वास्तव में रु. 4. 42 करोड़ (बैंक गारंटी का आह्वान करके), अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि मेसर्स इंसेक्टिसाइड्स एंड एलाइड केमिकल्स फर्म से धन का भुगतान किया गया था। इसलिए, विशेष अदालत ने पहले निष्कर्ष निकाला कि बी. एच. ई. एल. को गलत नुकसान हुआ और इसलिए, आई. पी. सी. की धारा 420 के तहत अपराध बनाया गया।

डी.

11. ट्रायल कोर्ट ने तब इस तर्क पर विचार किया कि पीडब्लू-16 (अप्रूवर) के कन्फेशन स्टेटमेंट को खारिज कर दिया जाना चाहिए, इस तथ्य को देखते हुए कि पीडब्लू-16 ने अपने कन्फेशन स्टेटमेंट में कुछ भी आत्म-दोषारोपण नहीं किया था। लेकिन ए-1 की ओर से पेश किए गए इस तर्क को अदालत ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रदर्शनी पी-26 वह चिट है जिसमें पीडब्लू-16 ने स्वीकार किया कि चार फर्जी फर्मों के नाम और मेसर्स एंटोमा हाइड्रो सिस्टम्स के नाम लिखे थे, जैसा कि ए-1 द्वारा निर्धारित किया गया था और यह यह दिखाने के लिए पर्याप्त था कि पीडब्लू-16 ए-1 के साथ आपराधिक साजिश के आरोप में खुद को दोषी ठहरा रहा था। 12. जब यह बताया गया कि अभिलेख पर साक्ष्य के अनुसार, पीडब्लू-1 अपनी सास की मृत्यु के कारण leave 26.11.1992 पर था और इसलिए, वह उस तारीख को कोई चर्चा नहीं कर सकता था, तो ट्रायल कोर्ट ने ए-1 के खिलाफ इस तर्क को बदल दिया और कहा कि ए-1 को प्रदर्शनी पी-27 के रूप में चिह्नित 25.11.1992 दिनांकित अनुमोदन नोट को मंजूरी नहीं देनी चाहिए थी, अगर वह छुट्टी पर था और उसने पृष्ठभूमि की जांच नहीं की थी।

ई.

च

जी.

13. इसके बाद निचली अदालत ने फैसला सुनाया कि अभियोजन पक्ष ने सफलतापूर्वक साबित कर दिया है कि जिन चार अन्य फर्मों के नाम चिट प्रदर्शनी पी-26 में पाए गए थे, वे सभी फर्जी थीं। यह पीडब्लू-2, पीडब्लू-3, पीडब्लू-5, पीडब्लू-6, पीडब्लू-7, पीडब्लू-9, पीडब्लू-10 और पीडब्लू-13 के साक्ष्य के आधार पर था।

एच.

30

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

14. पीडब्लू-16 के कथन को सही मानते हुए, विशेष अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ए-1 ने ए-5 को अनुबंध का पुरस्कार पूर्व निर्धारित किया और यह दिखाने के लिए परिस्थितियाँ और रिकॉर्ड बनाए कि जैसे कि उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था और इसलिए ए-1 आरोपों का दोषी था। 15. ए-2 के खिलाफ आरोपों पर आते हुए, विशेष अदालत ने कहा कि उनके द्वारा निभाई गई एकमात्र भूमिका दिनांकित अनुमोदन नोट तैयार करना था और ए-1 के खिलाफ भारी सबूत को देखते हुए, अनुबंध, किसी भी मामले में, संबंधित फर्म को दिया गया होगा। इसलिए, विशेष अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची (फैसले के पैराग्राफ 79 में) कि ए-2 को केवल ए-1 और साजिश में काम करने वाले अनुमोदनकर्ता द्वारा तैयार की गई सूची को विश्वसनीयता देने के लिए प्रदर्शनी पी-27 में हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया था। इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद, विशेष अदालत ने ए-2 को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया।

ग

16. जहां तक ए-3 और ए-4 का संबंध है, यह तर्क दिया गया कि वे ए-3, ए-4 और अनुमोदनकर्ता वाली वार्ता समिति के गठन के बाद ही सामने आए। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इस तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जो गठित किया गया था वह एक निविदा समिति थी, जैसा कि प्रदर्शनी पी-36 (समिति की कार्यवाही) से देखा गया है और इसलिए यदि वे निर्दोष थे, तो उन्हें ठेकेदारों के बारे में पूछताछ करनी चाहिए थी और विवरण मांगना चाहिए था। दिलचस्प बात यह है कि ट्रायल कोर्ट ने पैराग्राफ 79 में यह अभिनिर्धारित करने के बाद कि ए-2 के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए थे, तर्क को उलटते हुए ए-3 और ए-4 को दोषी ठहराने के बाद फिर से ए-2 के अपराध के सवाल पर वापस चला गया। 17. ए-7 द्वारा निभाई गई भूमिका पर आते हुए, ट्रायल कोर्ट ने कहा कि यह वही था जिसने बी. एच. ई. एल. को धोखा देने के उद्देश्य से फर्जी फर्मों के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट खरीदे थे और उसने फर्म इंसेक्टिसाइड्स एंड एलाइड केमिकल्स के भागीदार के रूप में अपने लिए गलत लाभ प्राप्त किया था। इन निष्कर्षों के आधार पर, निचली अदालत ने पैराग्राफ 4 के तहत तालिका में हमारे द्वारा उल्लिखित अपराधों के लिए अभियुक्तों

को दोषी ठहराया और उन्हें पैराग्राफ 5 के तहत तालिका में दर्शाए गए कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। 18.ए-1, ए-3, ए-4 और ए-7 द्वारा दायर अपीलों पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने उन्हें दो श्रेणियों में विभाजित किया, पहला ए-1, ए-3 और ए-4 की जटिलता से संबंधित और दूसरा ए-7 की जटिलता से संबंधित। शायद यही कारण था कि ए-1, ए-3 और ए-4 बी. एच. ई. एल. के अधिकारी थे, जबकि ए-7 एक निजी व्यक्ति था।

डी.

ई.

च

जी.

19. ए-1, ए-3 और ए-4 की संलिप्तता पर, उच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से केंद्रीय ए के तकनीकी परीक्षक पीडब्लू-8 के साक्ष्य पर भरोसा किया।

एच.

31

ए. श्रीनिवासुलु बनाम राज्य प्रतिनिधि. पुलिस निरीक्षक द्वारा [वी. रामसुब्रमणियन, जे.] ए.

सतर्कता आयोग के साथ-साथ पी. डब्ल्यू.-16, अनुमोदनकर्ता का साक्ष्य। दस्तावेजों द्वारा समर्थित उनके साक्ष्य के आधार पर, उच्च न्यायालय ने माना कि ए-1, ए-3 और ए-4 की संलिप्तता साबित हुई थी। यह पूछे जाने पर कि क्या अभियुक्त की कार्रवाई के परिणामस्वरूप बी. एच. ई. एल. को मौद्रिक नुकसान हुआ, उच्च न्यायालय ने कहा कि बी. एच. ई. एल. द्वारा बैंक गारंटी का आह्वान करके और धन की प्राप्ति करके किए गए उपचारात्मक उपाय से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि कोई गलत नुकसान नहीं हुआ था।

20. जहां तक ए-7 की संलिप्तता का संबंध है, उच्च न्यायालय ने कहा कि निविदा दस्तावेज प्राप्त करने के लिए डिमांड ड्राफ्ट प्राप्त करने के लिए विभिन्न बैंकों को प्रस्तुत आवेदनों में निहित हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से ए-7 के थे। वास्तव में, डिमांड ड्राफ्ट प्राप्त करने के लिए आवेदनों को प्रदर्शनी पी-66, पी-76, पी-90 और पी-92 के रूप में चिह्नित किया गया था और इन प्रदर्शनों को उनकी राय के लिए एक हस्तलेखन विशेषज्ञ को भेजा गया था। हस्ताक्षर विशेषज्ञ की जांच पीडब्लू-30 के रूप में की गई। उनकी रिपोर्ट को प्रदर्शनी पी-68 के रूप में चिह्नित किया गया था। ए-7 के नमूना लेखन और हस्ताक्षरों को पीडब्लू-30 के माध्यम से प्रदर्शनी पी-75 के रूप में चिह्नित किया गया था।

ग

डी.

21. लेकिन उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले के पैराग्राफ 44 में पाया कि हस्तलेखन विशेषज्ञ ने अपनी रिपोर्ट में प्रदर्शनी पी-75 में पाए गए लेखन की तुलना मांग मसौदा आवेदन पत्र प्रदर्शनी पी-66, पी-76, पी-90 और पी-92 के साथ करने के बारे में कोई राय नहीं दी थी। उच्च न्यायालय ने यह भी पाया (विवादित फैसले के पैराग्राफ 49 में) कि हस्ताक्षर विशेषज्ञ द्वारा स्वीकार किए गए हस्ताक्षर और हस्ताक्षर की तुलना नहीं की गई थी। इस तरह के निष्कर्ष को दर्ज करने के बाद, उच्च न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 को लागू करके खुद से तुलना करने का काम संभाला। धारा 73 को लागू करते हुए, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मांग मसौदा आवेदनों में पाए गए हस्ताक्षर ए-7 के थे और धन का हस्तांतरण एम / एस. कीटनाशक और संबद्ध रसायन एक ऐसी परिस्थिति है जो इसकी पुष्टि करती है।

ई.

च

22. ए-3 और ए-4 की ओर से उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया कि बी. एच. ई. एल. प्रशासन ने पी. सी. अधिनियम के तहत अपराधों के लिए उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया था और इसलिए उन्हें अन्य अपराधों का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन इस तर्क को उच्च न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि कंपनी के प्रबंधन द्वारा लिए गए निर्णय का अभियोजन मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है।

जी.

23. उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर, उच्च न्यायालय ने अपीलों को खारिज कर दिया और निचली अदालत द्वारा दी गई दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की।

एच.

32

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

24. ए-1 की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री हुजेफा अहमदी ने तर्क दिया:- -प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

(i) कि ए-1 को किसी भी अपराध के किए जाने से जोड़ने के लिए कोई सबूत नहीं था और कोई भी आरोप उचित संदेह से परे स्थापित नहीं हुआ था;

((ii) कि आरोपों का आधार पूरी तरह से सरकारी गवाह (पीडब्लू-16) के बयान पर आधारित था, लेकिन वह गंभीर अनियमितताओं से ग्रस्त है;

(iii) यद्यपि अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने से पहले उनकी सेवानिवृत्ति को देखते हुए पीसी अधिनियम के तहत अपराधों के लिए ए-1 पर मुकदमा चलाने के लिए किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी, संहिता की धारा 197 (1) के तहत पूर्व मंजूरी आवश्यक थी, लेकिन वह प्राप्त नहीं की गई थी; और

ग

((iv)) कि अभियोजन पक्ष आवश्यक स्थापित करने में विफल रहा

"अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त करने" का घटक

डी.

उसे पी. सी. अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) के तहत अपराधों का दोषी ठहराने के लिए।

25. ए-4 की ओर से पेश होते हुए विद्वान वकील श्री एस. आर. रघुनाथन ने तर्क दिया:- -प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

(i) कि ए-4 ने निविदा तैयार करने या निविदाकारों के चयन में कोई भूमिका नहीं निभाई;

ई.

((ii) ए-1 के कहने पर कथित तौर पर पीडब्लू-16 द्वारा निविदाकारों को चुने जाने के बाद, जो 23.12.1992 पर गठित किया गया था, वह केवल एक वार्ता समिति थी;

च

((ग) ए-3, ए-4 और पीडब्लू-16 नामक तीन सदस्यों वाली उक्त समिति में वह (ए-4) वह था जो अन्य दो सदस्यों के अधीनस्थ था और इसलिए ए-2 पर लागू तर्क उसे भी दिया जाना चाहिए था; (iv) कि विशेष न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने पीडब्लू-14 के साक्ष्य की इस आशय से अनदेखी की कि कोई निविदा समिति गठित नहीं की गई थी;

जी.

(v) कि बी. एच. ई. एल. को कोई गलत नुकसान नहीं हुआ था;

(vi) कि इसके विपरीत, ए-4 द्वारा निभाई गई भूमिका के कारण, रु। एंटोमा हाइड्रो सिस्टम से 4 करोड़ 84 लाख रुपये प्राप्त किए गए।

एच.

33

ए. श्रीनिवासुलु बनाम राज्य प्रतिनिधि. पुलिस निरीक्षक द्वारा [वी. रामसुब्रमणियन, जे.] ए.

((viii) कि बैंक गारंटी का उपयोग किया गया था और बी. एच. ई. एल. द्वारा संचित अग्रिम के लिए भुगतान की गई पूरी राशि की वसूली की गई थी; (viii) कि वास्तव में रु. बी. एच. ई. एल. द्वारा बैंक गारंटी लागू करने और खातों के मिलान के बाद एंटोमा हाइड्रो सिस्टम को 26 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है।

(ix) कि सी. बी. आई. के बार-बार अनुरोध के बावजूद, बी. एच. ई. एल. के प्रबंधन ने ए-3 और ए-4 पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इस आधार पर इनकार कर दिया कि उन्होंने कंपनी के सर्वोत्तम वाणिज्यिक हित में काम किया; और

(x) कि एक बार ए-4 को धारा 120 बी के तहत अपराध का दोषी नहीं ठहराया जाता है, तो उसे अन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराना संभव नहीं था, विशेष रूप से मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में।

ग

26. ए-7 की ओर से पेश होते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एस. नागमुथु ने तर्क दिया:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

(i) कि पीडब्लू-16 का स्वीकारोक्ति बयान XVIII मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चेन्नई द्वारा दर्ज किया गया था, लेकिन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मदुरै द्वारा माफी दी गई थी और अंतिम रिपोर्ट सीधे सीबीआई मामलों के लिए विशेष अदालत के समक्ष दायर की गई थी;

ई.

(ii) कि चूंकि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस मामले में माफी प्रदान की है, इसलिए यह मामला धारा 306 की उप-धारा (1) के दायरे में आता है और इसलिए अभियोजन पक्ष को संहिता की धारा 306 (4) (ए) के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था।

च

(iii) कि इस बात का कोई विशेष कारण नहीं है कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष माफी के लिए याचिका क्यों दायर की गई थी, जब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकारोक्ति बयान दर्ज किया गया था और कोई कारण नहीं है कि अभियोजन पक्ष ने पीसी अधिनियम 1988 की धारा 5 (1) के तहत सीधे विशेष अदालत के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दायर करने का विकल्प चुना; (iv) कि न तो पीडब्लू-44 (आई. ओ.) के साक्ष्य और न ही पीडब्लू-16 (अनुमोदनकर्ता) के साक्ष्य में ए-7 को दोष देने वाला कुछ भी नहीं था;

जी.

(v) कि ए-7 को शामिल किया गया है, केवल ए-5 के साथ उनके संबंधों के कारण और कुल राशि के कारण भी।

एच.

34

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

एंटोमा हाइड्रो सिस्टम के खाते से उस फर्म को हस्तांतरित किया जा रहा है जिसमें वह एक भागीदार है।

((vi) कि विशेष न्यायालय, प्रदर्शनी पी-68 के रूप में चिह्नित हस्तलेखन विशेषज्ञ की रिपोर्ट में गए बिना और प्रदर्शनी पी-75 के रूप में चिह्नित उनके नमूना हस्ताक्षरों के संबंध में संहिता की धारा 313 के तहत ए-7 से कोई सवाल किए बिना इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मांग मसौदे के लिए आवेदनों में उनकी लिखावट और हस्ताक्षर थे, उच्च न्यायालय ने उक्त तर्क को खारिज कर दिया, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 73 के तहत उपलब्ध मार्ग को अपनाया।(vii) कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 के तहत प्रक्रिया अदालत के लिए केवल तभी उपलब्ध है जब स्वीकार किए गए या सिद्ध हस्तलेखन हों, जो इस मामले में अनुपस्थित थे;

ग

(viii) कि किसी भी मामले में बी. एच. ई. एल. को कोई नुकसान नहीं हुआ था, जो कि पी. सी. अधिनियम के तहत अपराध के लिए एक अनिवार्य शर्त है; और (ix) कि एक अजीब तर्क से ए-7 को पी. सी. अधिनियम की धारा 13 (1) (ई) के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था।

डी.

27. अपीलार्थियों की ओर से की गई दलीलों का विरोध करते हुए, राज्य के विद्वान वकील श्री पद्मेश मिश्रा ने तर्क दिया:(i) सभी अभियुक्तों को उन अपराधों से जोड़ने के लिए मौखिक और दस्तावेजी दोनों तरह के ठोस साक्ष्य थे जिनके लिए वे दोषी पाए गए थे;

ई.

((ख) अनुमोदनकर्ता (पीडब्लू-16) के साक्ष्य की पुष्टि अन्य गवाहों की गवाही से सभी पहलुओं जैसे कि सीमित निविदा के लिए जाने का जानबूझकर किया गया कार्य, उस व्यक्ति का पूर्वनिर्धारण करना जिसके पक्ष में अनुबंध दिया जाना था, सामान्य व्यावसायिक मानदंड से कहीं अधिक ब्याज मुक्त जुटाने वाले अग्रिम की मंजूरी, ठेकेदार द्वारा इस तरह के अग्रिम को किसी अन्य फर्म में स्थानांतरित करना जिसमें वह पिता और भाई के साथ भागीदार था और इन कदाचारों के कारण अनुबंध को अंततः समाप्त करना;

च

जी.

((ग) कानून में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि पी. सी. अधिनियम की धारा 13 (1) (घ) के तहत किसी अपराध के लिए वास्तविक नुकसान उठाना पड़ा हो।

एच.

35

ए. श्रीनिवासुलु बनाम राज्य प्रतिनिधि. पुलिस निरीक्षक द्वारा [वी. रामसुब्रमणियन, जे.] ए.

(iv) कि किसी भी मामले में बैंक गारंटी के आह्वान से जो बरामद किया गया था, वह पहली बार में हुआ नुकसान था; (v) यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि संहिता की धारा 197 (1) के तहत मुकदमा चलाने के लिए पूर्व मंजूरी केवल तभी आवश्यक है जब शिकायत किया गया कार्य आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में हो; (vi) कि धोखाधड़ी के अपराध को किसी भी तरह से आधिकारिक कर्तव्यों के हिस्से के रूप में नहीं देखा जा सकता है;

((vii) कि क्षमा प्रदान करने की शक्ति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/महानगर मजिस्ट्रेट के साथ-साथ सत्र न्यायालय के लिए भी उपलब्ध है;

ग

(viii) कि इसलिए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मदुरै द्वारा क्षमा प्रदान करने में कुछ भी गलत नहीं था; और (ix) इसलिए अपीलार्थियों को दोषी ठहराने के समवर्ती निर्णय किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देते हैं।

डी.

28. हमने प्रतिद्वंद्वी विवादों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। आसानी से मूल्यांकन के उद्देश्य से, हम चर्चा और विश्लेषण को तीन भागों में विभाजित करेंगे, पहला संहिता की धारा 197 के इर्द-गिर्द घूमने वाले विवाद से संबंधित, दूसरा संहिता की धारा 305 के तहत क्षमा प्रदान करते समय अपनाई गई प्रक्रिया की शुद्धता से संबंधित और तीसरा हमारे सामने प्रत्येक अपीलार्थी की दोषसिद्धि के मामले के गुण-दोष के इर्द-गिर्द घूमता है।

ई.

चर्चा और विश्लेषण

भाग-I (संहिता की धारा 197 के इर्द-गिर्द घूमना)

29. इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि ए-1 से ए-4, आई. पी. सी. की धारा 21 की बारहवीं मद में निहित विवरण के भीतर आने वाली कंपनी के अधिकारी होने के नाते, आई. पी. सी. की धारा 21 के तहत उक्त अभिव्यक्ति की परिभाषा के भीतर 'लोक सेवक' थे। ए-1 से ए-4 भी पी. सी. अधिनियम की धारा 2 (सी) (iii) के तहत अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर लोक सेवक थे। इसलिए, आई. पी. सी. और पी. सी. अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के लिए ए-1 से ए-4 तक का मुकदमा चलाने के लिए संहिता की धारा 197 (1) और पी. सी. अधिनियम की धारा 19 (1) दोनों के तहत पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है।

च

जी.

30. भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का अधिनियम 16) के तहत पी. सी. अधिनियम में संशोधन होने तक, धारा 19 (1) (ए) के तहत पिछली मंजूरी की आवश्यकता होती है।

एच.

36

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

यह केवल एक ऐसे व्यक्ति तक सीमित था जो "नियोजित है"। इसके विपरीत, धारा 197 (1) ने पूर्व मंजूरी की आवश्यकता को आवश्यक बना दिया,

"किसी भी व्यक्ति के संबंध में" और "किसी भी व्यक्ति के संबंध में" दोनों

जो "नियोजित" था। 2018 के अधिनियम 16 के तहत संशोधन द्वारा, पी. सी. अधिनियम की धारा 19 (1) (ए) को उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया था ताकि किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में भी पूर्व मंजूरी आवश्यक हो जाए जो "कार्यस्थल पर कार्यरत था।

अपराध करने का समय "।

31. यह मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का अधिनियम 16) के लागू होने से पहले उठा था। इसलिए, जहां तक ए-1 का संबंध है, पीसी अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत कोई पूर्व मंजूरी आवश्यक नहीं थी, क्योंकि अंतिम रिपोर्ट दाखिल होने तक वह सेवानिवृत्त हो चुके थे। ओ. वास्तवमे एफ. आई. आर. दर्ज करबाक 7 मास (31.01.1997) आ अन्तिम रिपोर्ट दाखिल करबासँ 5 वर्ष पहिने (16.07.2002) आ विशेष न्यायालय द्वारा संज्ञान लेबाक 6 वर्ष पहिने (04.07.2003) 31.08.1997 पर सेवानिवृत्त भऽ गेलाह। लेकिन ए-3 और ए-4 के संबंध में पीसी अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत पूर्व मंजूरी की आवश्यकता थी, क्योंकि वे विशेष न्यायालय के संज्ञान लेने के समय सेवा में थे। इसलिए एजेंसी ने मंजूरी मांगी, लेकिन बी. एच. ई. एल. के प्रबंधन ने एक बार नहीं बल्कि दो बार मंजूरी देने से इनकार कर दिया, जहां तक ए-3 और ए-4 का संबंध है। 32. ए-3 और ए-4 द्वारा अपने नियोक्ता से प्राप्त परोपकार ए-1 के लिए भाग्य की विचित्रता या एक समय में पैदा होने (और परिणामस्वरूप एक विशेष समय पर सेवानिवृत्त होने) की दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के कारण उपलब्ध नहीं था। यदि वह सेवा में बने रहते, तो बी. एच. ई. एल. द्वारा लिए गए रुख को देखते हुए उन पर पी. सी. अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था।

ग

डी.

ई.

33. ऐसा प्रतीत होता है कि बी. एच. ई. एल. ने कारण बताते हुए आई. डी. 2 दिनांकित एक पत्र द्वारा मंजूरी देने से इनकार कर दिया, लेकिन सी. वी. सी. ने आई. डी. 1 दिनांकित एक पत्र के माध्यम से जोर दिया। उसी के जवाब में, बी. एच. ई. एल. के सी. एम. डी. ने एक नया रूप लिया। इसके बाद, दिनांक 1 के एक निर्णय द्वारा, उन्होंने इस आधार पर मंजूरी देने से इनकार कर दिया कि यह कंपनी के वाणिज्यिक हित में नहीं होगा और न ही सार्वजनिक उपक्रम में कुशल, त्वरित और अनुशासित काम करने के सार्वजनिक हित में होगा।

च

जी.

34. संहिता की धारा 197 (1) के तहत पूर्व मंजूरी की आवश्यकता के इर्द-गिर्द घूमने वाले तर्क पर उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए। यह सच है कि ए-3 और ए-4 के संबंध में पी. सी. अधिनियम के तहत अभियोजन के लिए मंजूरी देने से इनकार करने का ए-1 के अभियोजन पर सीधा असर नहीं पड़ सकता है। लेकिन यह निश्चित रूप से ए प्रदान करेगा एच.

37

ए. श्रीनिवासुलु बनाम राज्य प्रतिनिधि. पुलिस निरीक्षक द्वारा [वी. रामसुब्रमणियन, जे.] ए.

जिस संदर्भ में आई. पी. सी. और पी. सी. अधिनियम दोनों के तहत अपराधों के लिए ए-1 की दोषीता का निर्धारण किया जाना है।

35. प्रत्यर्थी-राज्य द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि ए-1 पर मुकदमा चलाने के लिए संहिता की धारा 197 (1) के तहत कोई पूर्व मंजूरी नहीं मांगी गई थी। अभियोजन पक्ष का रुख यह है कि धारा 197 (1) के तहत पूर्व मंजूरी केवल तभी आवश्यक हो सकती है जब अपराध कथित रूप से किया गया हो।

अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करना या कार्य करना।

धारा 197 (1) पर लगभग सभी न्यायिक उदाहरणों ने इन शब्दों को बदल दिया है। इसलिए, अब हम कुछ निर्णयों पर एक त्वरित लेकिन संक्षिप्त नज़र डाल सकते हैं।

36. डॉ. होरी राम सिंह बनाम। क्राउन 3 का निर्णय है

ग

संघीय न्यायालय, कई निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया है। यह सत्र न्यायालय के फैसले के खिलाफ लाहौर उच्च न्यायालय के फैसले से उत्पन्न हुआ, जिसने अपीलार्थी को राज्यपाल की सहमति के अभाव में आईपीसी की धारा 409 और 477 ए के तहत आरोपों से बरी कर दिया था। सर एस. वरदाचारियार, जिनकी राय के साथ ग्वायर सी. जे. ने सहमति व्यक्त की, जांच की

डी.

शब्द, "निष्पादन में किया गया कोई कार्य या किया जाना अभिप्रेत है।

भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 270 (1) में दिखाई देने वाले अपने कर्तव्य के बारे में, जिसके लिए राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता थी। संघीय

न्यायालय ने शुरुआत में कहा कि यह प्रश्न काफी हद तक एक तथ्य है, जिसे शिकायत किए गए अधिनियम के संदर्भ में निर्धारित किया जाना चाहिए और

परिचर परिस्थितियाँ। संघीय न्यायालय ने तब संहिता की धारा 197 के तहत कई फैसलों को सादृश्य के रूप में संदर्भित किया और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ई.

“सेक के आवेदन पर रिपोर्ट किए गए निर्णय। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 किसी भी तरह से समान नहीं है। उनमें से अधिकांश में, प्रत्येक सहजता के तथ्यों को देखते हुए, वास्तविक निष्कर्ष शायद अप्रत्याशित पाया जाएगा; लेकिन, कुछ में, परीक्षण को ऐसे संदर्भों में निर्धारित किया गया है जिन्हें संपूर्ण या सही के रूप में स्वीकार करना मुश्किल है। इंग्लैंड में भाषा पर, समान वैधानिक प्रावधानों के निर्णयों के बारे में भी यही कहा जा सकता है (बूथ बनाम क्लाइव में टिप्पणियाँ देखें) करता है।

च

जी.

धारा के तहत दिए गए निर्णयों की विस्तार से समीक्षा करना मुझे आवश्यक नहीं लगता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197, जिसे मोटे तौर पर तीन समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जहाँ तक कि उन्होंने एक की प्रकृति में कुछ कहने का प्रयास किया है।

3 1939 एस. सी. सी. ऑनलाइन एफ. सी. 2

एच.

38 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

परीक्षण। मामलों के एक समूह में, इस बात पर जोर दिया जाता है कि शिकायत किए गए अधिनियम की प्रकृति में कुछ ऐसा होना चाहिए जो इसे करने वाले व्यक्ति के आधिकारिक चरित्र से जोड़ता है: सी. एफ. शेख अब्दुल खादिर साहब; कामिसेट्टी राजा राव बनाम रामास्वामी, अमानत अली बनाम राजा-सम्राट, राजा-सम्राट बनाम मौंग बो मौंग और गुरुसिदया शांतिविरय्या कुलकर्णी बनाम राजा-सम्राट। एक अन्य समूह में, इस परिस्थिति पर अधिक जोर दिया गया है कि अभियुक्त के आधिकारिक

चरित्र या स्थिति ने उसे अपराध करने का अवसर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि पहला दृष्टिकोण सही है। मामलों के तीसरे समूह में, लगभग विशेष रूप से इस तथ्य पर जोर दिया जाता है कि यह ऐसे समय में था जब आरोपी अपने आधिकारिक कर्तव्य में लगा हुआ था कि कथित अपराध किया गया था जैसा कि कहा जाता है [गंगाराजू बनाम वेंकी देखें, मित्रा की टिप्पणी (आपराधिक प्रक्रिया संहिता) से उद्धृत करते हुए। सेक में "अभिनय करते समय" आदि अभिव्यक्ति का उपयोग। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 (विशेष रूप से 1923 में संशोधन के माध्यम से इसकी शुरुआत) को इस दृष्टिकोण को कुछ समर्थन देने के लिए माना गया है। हालांकि मैं समय कारक के महत्व को नजरअंदाज नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे इसे परीक्षण बनाना सही नहीं लगता है। तर्क के दौरान सुझाए गए एक उदाहरण को लेने के लिए, यदि किसी चिकित्सा अधिकारी पर अस्पताल में ड्यूटी के दौरान किसी मरीज के साथ बलात्कार करने या मरीज के व्यक्ति से गहना चुराने का आरोप लगाया जाता है, तो यह विश्वास करना मुश्किल है कि यह विधानमंडल का इरादा था कि स्थानीय सरकार की पूर्व मंजूरी के अलावा ऐसे अपराधों के लिए उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था।

ग

डी.

ई.

च

37. ऊपर निकाले गए निर्णय के हिस्से से यह देखा जाता है कि संघीय न्यायालय ने डॉ. होरी राम सिंह (ऊपर) में संहिता की धारा 197 के तहत दिए गए निर्णयों को तीन समूहों में वर्गीकृत किया है।

अर्थात् (i) ऐसे मामले जहां यह अभिनिर्धारित किया गया था कि शिकायत किए गए कार्य की प्रकृति में कुछ ऐसा होना चाहिए जो इसे करने वाले व्यक्ति के आधिकारिक चरित्र से जोड़ता है; (ii) ऐसे मामले जहां इस परिस्थिति पर अधिक जोर दिया गया है कि अभियुक्त के आधिकारिक चरित्र या स्थिति ने उसे अपराध करने का अवसर दिया है; और (iii) ऐसे मामले जहां लगभग विशेष रूप से इस तथ्य पर जोर दिया गया है कि यह उस समय था जब अभियुक्त ए.

जी.

एच.

39

ए. श्रीनिवासुलु बनाम राज्य प्रतिनिधि. पुलिस निरीक्षक द्वारा [वी. रामसुब्रमणियन, जे.] ए.

अपने आधिकारिक कर्तव्य में लगे हुए थे कि कथित अपराध था

कहा जाता है कि प्रतिबद्ध किया गया है। मामलों की पहली श्रेणी में निर्धारित परीक्षण को प्राथमिकता देते हुए, संघीय न्यायालय ने तीसरी श्रेणी के मामलों में दिए गए परीक्षण को खारिज कर दिया, जिसमें एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा अपने किसी एक रोगी के साथ बलात्कार करने या रोगी के व्यक्ति से रत्न की चोरी करने का चित्रण किया गया था।

38. माटाजोग डोबे बनाम एच. सी. भरी 4 में इस न्यायालय की संविधान पीठ इन शब्दों की व्याख्या से संबंधित थी,

“ धारा 197 में "अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुए उसके द्वारा किया गया कोई भी अपराध"

कोड से। डॉ. होरी राम सिंह में निर्णय का उल्लेख करने के बाद संविधान पीठ ने चर्चा के परिणाम को पैराग्राफ में संक्षेप में प्रस्तुत किया।

ग

19 धारण करके: “अधिनियम और आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन के बीच एक उचित संबंध होना चाहिए; अधिनियम को कर्तव्य के साथ ऐसा संबंध रखना चाहिए कि अभियुक्त एक उचित, लेकिन एक ढोंग या काल्पनिक दावा नहीं कर सके, कि उसने इसे अपने कर्तव्य के प्रदर्शन के दौरान किया था।”

डी.

39. उड़ीसा राज्य में कुमार राघवेंद्र सिंह बनाम.

इस न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ गणेश चंद्र ज्यू 5 ने समझाया कि धारा 197 के तहत संरक्षण की कुछ सीमाएँ हैं और यह केवल तभी उपलब्ध है जब कथित कार्य उचित रूप से अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से जुड़ा हो और यह केवल आपत्तिजनक कार्य करने के लिए एक लबादा नहीं है। न्यायालय ने यह भी समझाया कि यदि वह अपने आधिकारिक कर्तव्य का पालन करते हुए अपने कर्तव्य से अधिक कार्य करता है, लेकिन कार्य और आधिकारिक कर्तव्य के प्रदर्शन के बीच एक उचित संबंध है, तो अतिरिक्त कार्य लोक सेवक को सुरक्षा से वंचित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगा।

ई.

च

40. उड़ीसा राज्य (ऊपर) में उपरोक्त निर्णय का पालन (संयोग से उसी लेखक द्वारा) के. कलिमुथु बनाम राज्य में किया गया था।

डीएसपी 6 और राकेश कुमार मिश्रा बनाम बिहार राज्य 7. 41. देविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में सी. बी. आई. 8 के माध्यम से यह

न्यायालय ने इस मुद्दे पर लगभग सभी निर्णयों पर ध्यान दिया और पैराग्राफ 39 में इससे उभरने वाले सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत किया:

जी.

4 (1955) 2 एससीआर 925 5 (2004) 8 एससीसी 40:6 (2005) 4 एससीसी 512 7 (2006) 1 एससीसी 557 8 (2016) 12 एससीसी 87

एच.

40 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

“39. उपरोक्त निर्णयों से उभरने वाले सिद्धांतों का सारांश नीचे दिया गया है:

39.1. मंजूरी का संरक्षण एक ईमानदार और ईमानदार अधिकारी को ईमानदारी से और सार्वजनिक कर्तव्य को आगे बढ़ाने की अपनी क्षमता के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करने का आश्वासन है। हालाँकि, अधिकार को अपराध करने के लिए छुपाया नहीं जा सकता है।

39.2. एक बार जब लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में कार्य या चूक पाई जाती है, तो इसे उदार और व्यापक रूप से बनाया जाना चाहिए जहां तक इसकी आधिकारिक प्रकृति का संबंध है। लोक सेवक आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने का हकदार नहीं है। उस हद तक सी. आर. पी. सी. की धारा 197 को संकीर्ण रूप से और प्रतिबंधित तरीके से समझा जाना चाहिए। 39.3. यहां तक कि ऐसे मामले के तथ्यों में भी जब लोक सेवक ने अपने कर्तव्य का उल्लंघन किया है, यदि उचित संबंध है तो यह उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत सुरक्षा से वंचित नहीं करेगा। यह निर्धारित करने के लिए एक सार्वभौमिक नियम नहीं हो सकता है कि क्या किए गए कार्य और आधिकारिक कर्तव्य के बीच उचित संबंध है और न ही इस तरह के नियम को निर्धारित करना संभव है।

डी.

39.4. यदि हमला आंतरिक रूप से आधिकारिक कर्तव्यों के प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है या संबंधित है, तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **197** के तहत मंजूरी आवश्यक होगी, लेकिन कर्तव्य के साथ इस तरह के संबंध को ढोंग या काल्पनिक दावा नहीं होना चाहिए। अपराध को मंजूरी की आवश्यकता के लिए सीधे और उचित रूप से आधिकारिक कर्तव्य से जुड़ा होना चाहिए। अपराध करना आधिकारिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं है। यदि अपराध बिना साबित किए अधूरा था, तो आधिकारिक अधिनियम, आमतौर पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **197** के प्रावधान लागू होंगे।

ई.

च

... ."

42. डी. देवराज बनाम ओवैस साबिर हुसैन **9** में, यह न्यायालय

व्याख्या की गई कि मंजूरी की आवश्यकता न केवल आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किए गए कार्यों के लिए है, बल्कि आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किए जाने वाले किसी भी कार्य और/या ऐसे कर्तव्य या प्राधिकरण के रंग या उससे अधिक के तहत किए गए कार्य के लिए भी आवश्यक है। इस न्यायालय ने यह भी कहा कि यह तय करने के लिए कि क्या मंजूरी आवश्यक है, परीक्षण यह है कि क्या अधिनियम पूरी तरह से आधिकारिक कर्तव्य से असंबद्ध है या क्या आधिकारिक कर्तव्य के साथ कोई उचित संबंध है।

जी.

9 (2020) 7 एससीसी 695 ए

एच.

41

ए. श्रीनिवासुलु बनाम राज्य प्रतिनिधि. पुलिस निरीक्षक द्वारा [वी. रामसुब्रमणियन, जे.] ए.

43. उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, यदि हम मामले के तथ्यों पर वापस जाते हैं, तो यह देखा जा सकता है कि ए-1 के खिलाफ प्राथमिक आरोप यह है कि ए-5 को अनुचित और अनुचित लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से, उन्होंने पीडब्लू-16 को चार फर्जी कंपनियों के नाम, चुने हुए के नाम के साथ निर्देशित करके सीमित निविदाओं के लिए जाने का निर्देश दिया और अंततः चुने हुए को अनुबंध प्रदान किया। अभियोजन पक्ष द्वारा यह स्वीकार किया गया कि प्रासंगिक समय पर, बी. एच. ई. एल. की कार्य नीति को प्रदर्शनी पी-11 के रूप में चिह्नित किया गया है, जिसमें तीन प्रकार की निविदाओं के लिए प्रावधान किया गया है, अर्थात् (i) खुली निविदा; (ii) सीमित/प्रतिबंधित निविदा; और (iii) एकल निविदा। **44.** अनुच्छेद 4.2।1 प्रदर्शनी पी-11 के रूप में दायर कार्य नीति और अभियोजन पक्ष द्वारा इस बात पर भरोसा किया गया कि एक नियम के रूप में, केवल रु. 1,00,000 तक काम करता है-प्रतिबंधित निविदा द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। तथापि, अनुच्छेद 4.2।1 इसमें एक सवार भी था जो इस प्रकार है:

ग

" **4.2.1** ... हालांकि रुपये से अधिक के मामलों में भी-यदि तात्कालिकता या किसी अन्य कारण से प्रतिबंधित निविदा का सहारा लेना आवश्यक महसूस किया जाता है, तो महाप्रबंधकों या इस उद्देश्य के लिए अधिकृत अन्य अधिकारियों के लिए कारण दर्ज करने के बाद ऐसा करने के लिए खुला रहेगा।"

डी.

45. ऊपर निकाली गई कार्य नीति के हिस्से से दो बातें स्पष्ट हैं। एक यह है कि नियम से विचलन की अनुमति थी। दूसरा यह है कि महाप्रबंधकों को भी कॉल लेने, सामान्य नियम से हटने और प्रतिबंधित निविदा का सहारा लेने के लिए अधिकृत किया गया

था। 46. मान लीजिए, ए-1 कार्यकारी निदेशक के पद पर था, जो महाप्रबंधक के पद से ऊपर था। उनके अनुसार उन्होंने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के साथ चर्चा करने के बाद प्रतिबंधित निविदा के लिए जाने का आह्वान किया था। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने पीडब्लू-28 के रूप में अपने साक्ष्य में इस संबंध में कोई चर्चा होने से इनकार किया।

ई.

च

47. यह पता लगाने के उद्देश्य से कि क्या ए-1 ने अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य किया या कथित रूप से कार्य किया, हमारे लिए यह देखने के लिए पर्याप्त है कि क्या वह किसी भी मौजूदा नीति के तहत सही या गलत तरीके से सुरक्षा ले सकता है। अनुच्छेद 4.2।1 ऊपर निकाली गई मौजूदा नीति से पता चलता है कि ए-1 के पास कम से कम एक तर्क योग्य मामला था, उस निर्णय के बचाव में जो उसने प्रतिबंधित निविदा के लिए लिया था। एक बार जब यह स्पष्ट हो जाता है, तो उसका कार्य, भले ही आरोप लगाया जाता है कि वह प्रामाणिक नहीं है या किसी साजिश के अनुसरण में है, उसके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में एक कार्य होगा, जिससे मामला संहिता की धारा 197 (1) के मापदंडों के भीतर आता है। इसलिए, अभियोजन पक्ष

जी.

एच.

42

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

पूर्व मंजूरी प्राप्त की होनी चाहिए थी। विशेष न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी इस पहलू पर अपना दिमाग नहीं लगाया।

48. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील श्री पद्मेश मिश्रा ने प्रकाश सिंह बादल बनाम पंजाब राज्य मामले में इस अदालत के फैसले के पैराग्राफ 50 में निहित अवलोकन पर पूरा भरोसा जताया। वह इस प्रकार है:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"50. धारा 420 के तहत धोखाधड़ी के अपराध या उस मामले के लिए धारा 467, 468, 471 और 120-बी से संबंधित अपराधों को उनकी प्रकृति से किसी भी कल्पना के विस्तार से किसी भी लोक सेवक द्वारा आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने के लिए किया गया माना नहीं जा सकता है। ऐसे मामलों में, आधिकारिक स्थिति केवल अपराध करने का अवसर प्रदान करती है।"

ग

49. उपरोक्त अवलोकन के आधार पर, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया था कि एक लोक सेवक द्वारा किया गया कोई भी कार्य, जो धोखाधड़ी का अपराध है, को आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते समय या कार्य करने के लिए किया गया नहीं माना जा सकता है।

डी.

50. लेकिन हमारी राय में उपरोक्त विवाद दूरागी है। प्रकाश सिंह बादल (ऊपर) में निर्णय के पैराग्राफ 50 में निहित टिप्पणियां प्रकृति में बहुत सामान्य हैं और इन्हें उक्त मामले से निकलने वाले अनुपात के रूप में नहीं माना जा सकता है। यदि उनके स्वभाव से, धारा 420, 468, 471 और 120 बी के तहत अपराधों को किसी लोक सेवक द्वारा आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने के लिए अभिप्रेत होने के रूप में नहीं माना जा सकता है, तो वही तर्क पीसी अधिनियम के तहत अपराधों के मामले में बहुत अधिक जोर से लागू होगा। संहिता की धारा 197 अपराधों के किसी भी ऐसे समूह को नहीं बताती है जो इसके दायरे से बाहर हो। इसलिए, प्रकाश सिंह बादल में निर्णय के पैरा 50 में निहित टिप्पणियों को न्यायिक रूप से एक

वैधानिक प्रिस्क्रिप्शन के लिए एक अपवाद के रूप में नहीं लिया जा सकता है। वास्तव में, प्रकाश सिंह बादल अनुमोदन के साथ अन्य निर्णयों (उसी विद्वान न्यायाधीश द्वारा लिखित) का हवाला देते हैं जहां इस न्यायालय ने एक अधिनियम के बीच अंतर किया, हालांकि कर्तव्य से अधिक, आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन के साथ यथोचित रूप से जुड़ा हुआ था और एक ऐसा कार्य जो केवल आपत्तिजनक कार्य करने के लिए एक लबादा था। दिलचस्प बात यह है कि राकेश कुमार मिश्रा (ऊपर) में दिए गए प्रस्ताव को निर्णय के पैराग्राफ 49 में अलग किया गया था।

ई.

च

जी.

एच.

10 (2007) 1 एससीसी 1 ए

43

ए. श्रीनिवासुलु बनाम राज्य प्रतिनिधि. पुलिस निरीक्षक द्वारा [वी. रामसुब्रमणियन, जे.] ए.

प्रकाश सिंह बादल मामले में, न्यायालय के समक्ष ऊपर निकाले गए पैराग्राफ 50 में टिप्पणियां की गईं।

51. किसी भी लोक सेवक को अपराध करने के लिए जनादेश या अधिकार के साथ नियुक्त नहीं किया जाता है। इसलिए, यदि प्रकाश सिंह बादल में निर्णय के पैराग्राफ 50 में निहित टिप्पणियों को लागू किया जाता है, तो कोई भी कार्य जो किसी भी कानून के तहत अपराध है, आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किसी अधिनियम के दायरे से बाहर हो जाएगा। इस प्रकार पूर्व मंजूरी की आवश्यकता को इस तरह की व्याख्या द्वारा निरर्थक बना दिया जाएगा।

52. यह याद रखना चाहिए कि इस विशेष मामले में, प्राथमिकी में वास्तव में केवल चार व्यक्तियों, अर्थात् पीडब्लू-16, ए-3, ए-4 और ए-5 को शामिल किया गया था। ए-1 को एफ. आई. आर. में शामिल नहीं किया गया था। वर्ष 1998 में पीडब्लू-16 द्वारा स्वीकारोक्ति बयान दिए जाने के बाद ही ए-1 को शामिल किया गया था। ए-1 के खिलाफ आरोप थे कि वह इन अपराधों को करने के लिए दूसरों के साथ आपराधिक साजिश में शामिल हो गया था। लेकिन बी. एच. ई. एल. के प्रबंधन ने दो बार ए-3 और ए-4 पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी देने से इस आधार पर इनकार कर दिया कि दिए गए निर्णय व्यावसायिक विवेक के दायरे में थे।

ग

डी.

कंपनी से। यदि कंपनी के प्रबंधन के अनुसार, सह-षड्यंत्रकारियों का वही कार्य वाणिज्यिक ज्ञान के दायरे में आता है, तो यह अकल्पनीय है कि ए-1 का कार्य, आपराधिक साजिश के हिस्से के रूप में, उसके सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन से बाहर था, ताकि उसे संहिता की धारा 197 (1) के तहत संरक्षण के लिए अयोग्य घोषित किया जा सके।

ई.

53. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम ए-1 की ओर से दिए गए इस तर्क को बरकरार रखते हैं कि अभियोजन पक्ष को आईपीसी के तहत अपराधों के लिए ए-1 पर मुकदमा चलाने के लिए संहिता की धारा 197 (1) के संदर्भ में पूर्व मंजूरी लेनी चाहिए थी।

च

भाग-II (क्षमा प्रदान करने के इर्द-गिर्द घूमना)

54. जैसा कि हमने कहीं और संकेत दिया है, के. भास्कर राव (वह व्यक्ति जो बाद में अप्रूवर बन गया) और ए-3 से ए-5 नामक 4 व्यक्तियों के खिलाफ 31.01.1997 पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। के. भास्कर राव, जो बाद में सरकारी गवाह बन गए, को अगस्त, 1998 में गिरफ्तार किया गया और स्वयं प्रतिवादियों द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया। अपनी रिहाई के बाद, उक्त के. भास्कर राव ने कोड की धारा 164 के तहत XVIII मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चेन्नई के समक्ष 16.11.1998 पर एक स्वीकारोक्ति बयान दिया। के. भास्कर राव द्वारा दिए गए बयान के आधार पर, अभियोजन पक्ष ने 2000 के आपराधिक एम. पी. No.562 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मदुरै के समक्ष माफी देने के लिए संहिता की धारा 376 के तहत एक याचिका दायर की। जिस पर

जी.

एच.

44

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मदुरै (जिन्हें यह सौंपा गया था) ने के. भास्कर राव को 17.07.2000 पर उनके सामने पेश होने के लिए बुलाया। के. भास्कर राव को उनकी कार्रवाई के परिणामों के बारे में व्यापक रूप से सूचित करने के बाद, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले को 18.07.2000 तक के लिए स्थगित कर दिया। आई. डी. 1 पर, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उनके इकबालिया बयान की सामग्री पढ़ी और भास्कर राव से पूछा कि क्या यह उनके द्वारा परिणाम जानने के बाद स्वेच्छा से दिया गया था। एक बार जब के. भास्कर राव ने सकारात्मक प्रश्नों का उत्तर दिया, तो अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने संहिता की धारा 306 के तहत के. भास्कर राव को माफी देने का आदेश जारी किया। इसके बाद, प्रतिवादियों ने मजिस्ट्रेट द्वारा मामला किए बिना सीधे सीबीआई मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश, चेन्नई के समक्ष 16.07.2002 पर एक अंतिम रिपोर्ट दायर की। चूंकि उपरोक्त के. भास्कर राव को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पहले ही माफी दे दी गई थी, इसलिए अभियोजन पक्ष ने सीबीआई मामलों के लिए विशेष अदालत के समक्ष पीडब्लू-16 के रूप में उनकी जांच की और (i) संहिता की धारा 164 के तहत के. भास्कर राव के बयान को प्रदर्शनी पी-44 के रूप में चिह्नित किया; (ii) संहिता की धारा 376 के तहत दायर याचिका की प्रति को प्रदर्शनी पी-51 के रूप में; और (iii) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मदुरै की कार्यवाही, क्षमा की निविदा से संबंधित, प्रदर्शनी पी-52 के रूप में।

ग

डी.

55. ए-7 की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एस. नागमुथु ने इस प्रकार अपनाई गई प्रक्रिया पर हमला किया। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को जांच, जांच या मुकदमे के दौरान माफी देने का अधिकार है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को किसी अपराध की जांच या मुकदमा चलाते समय माफी देने का अधिकार है। यह संहिता की धारा 306 की उप-धारा (1) के आधार पर है। मामले में, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जांच के चरण में माफी दे दी। इसलिए, विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि धारा 376 (1) द्वारा कवर किए गए मामलों में, अनुमोदक की दो बार जांच की जानी चाहिए, एक बार समर्पण से पहले और फिर मुकदमे के समय। इन दो चरणों में एक सरकारी गवाह की जाँच के बीच अंतर यह है कि सरकारी गवाह की जाँच से पहले अदालत के गवाह के रूप में की जाती है, लेकिन मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में की जाती है। इसलिए, विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि एक सरकारी गवाह की दो बार इस तरह की जांच, धारा 306 की उप-धारा (4) के खंड (ए) की एक अनिवार्य आवश्यकता है और यह निर्णय कई निर्णयों द्वारा लिया गया है कि धारा 306 (4) (ए) का पालन न करने से कार्यवाही दूषित हो जाएगी। यह विद्वान वरिष्ठ ए का तर्क है।

ई.

च

जी.

एच.

45

ए. श्रीनिवासुलु बनाम राज्य प्रतिनिधि. पुलिस निरीक्षक द्वारा [वी. रामसुब्रमणियन, जे.] ए.

अधिवक्ता ने कहा कि यदि मजिस्ट्रेट, जो क्षमा प्रदान करता है, सरकारी गवाह द्वारा माफी स्वीकार किए जाने के तुरंत बाद गवाह के रूप में उसकी जांच करने में विफल रहा है, तो सरकारी गवाह का साक्ष्य विचार से वंचित किया जा सकता है। विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस मामले में, पीडब्लू-18 के रूप में जांच किए गए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने संहिता की धारा 376 (4) (ए) की आवश्यकता का पालन नहीं किया था और इसलिए सरकारी गवाह का साक्ष्य टाल दिया जाना चाहिए।

56. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. नागमुथु ने यह भी प्रस्तुत किया कि दंडादेश देने से पहले एक बार अदालत के गवाह के रूप में और फिर मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में एक बार सरकारी गवाह से पूछताछ करने की आवश्यकता, जो संहिता की धारा 307 द्वारा कवर किए गए मामले में लागू नहीं होगी, जो उस न्यायालय को क्षमा देने का अधिकार देता है, जिसके लिए मामला परीक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन मामले में, मामला किसी भी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष न्यायालय को नहीं सौंपा गया था और इसलिए, अभियोजन संहिता की धारा 307 पर भी भरोसा नहीं कर सकता है।

ग

डी.

57. पी. सी. अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) और (2) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, वरिष्ठ वकील श्री एस. नागमुथु ने तर्क दिया कि माफी देने की शक्ति विशेष न्यायालय को भी उपलब्ध है। विशेष न्यायालय द्वारा इस प्रकार दी गई क्षमा को धारा 5 की उप-धारा (2) के तहत संहिता की धारा 307 के तहत दी गई क्षमा माना जाता है। लेकिन यह काल्पनिक धारणा संहिता की धारा 308 की उप-धारा (1) से (5) के प्रयोजनों के लिए ही सीमित है। दूसरे शब्दों में, संहिता की धारा 307 के तहत माफी देने की अदालत की शक्ति पीसी अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत विशेष अदालत की शक्ति से भौतिक रूप से अलग है। वास्तव में, पी. सी. अधिनियम की धारा 5 (1) विशेष न्यायालय को किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा मामले को किए बिना संज्ञान लेने का अधिकार देती है। इस प्रकार संहिता की धारा 193 के प्रावधान उनके आवेदन में बहिष्कृत हैं। इस प्रकार विशेष न्यायालय को पी. सी. अधिनियम की धारा 5 (1) द्वारा प्रदान किया जाता है, जो संज्ञान लेने के लिए मूल अधिकार क्षेत्र है। इस सिद्धांत को मान्यता दी गई है।

ई.

च

यह न्यायालय बंगारु लक्ष्मण बनाम राज्य (सी. बी. आई. के माध्यम से) **11** में, जिसमें यह

यह अभिनिर्धारित किया गया था कि विशेष न्यायाधीश के पास दोहरी शक्ति है, अर्थात् सत्र न्यायालय और मजिस्ट्रेट की। निर्णय पर निर्भर करते हुए

जी.

हर्षद एस. मेहता बनाम महाराष्ट्र राज्य **12** और पी. सी. में निर्णय मिश्रा बनाम राज्य (केंद्रीय जांच ब्यूरो) **13** और राज्य **11** (2012) 1 एससीसी 500 12 (2001) 8 एससीसी 257 13 (2014) 14 एससीसी 629

एच.

केंद्रीय जांच ब्यूरो, चेन्नई बनाम वी. अरुल के माध्यम से

कुमार 14, विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि इस मामले में माफी का अनुरोध केवल विशेष अदालत के समक्ष जांच के चरण में किया जाना चाहिए था। यह मानते हुए भी कि यह एक उपचार योग्य दोष था, पीडब्लू-18 (अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) की ओर से सद्भावना का प्रमाण होना चाहिए। इस तरह के साक्ष्य के अभाव में, यह तर्क दिया जाता है कि इस मामले में सरकारी गवाह की गवाही से बचा जा सकता है।

58. हमने उपरोक्त प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है।

59. इससे पहले कि हम अपने विश्लेषण के साथ आगे बढ़ें, संहिता की धारा 30 और 307 और पी. सी. अधिनियम की धारा 5 को रिकॉर्ड पर लाना आवश्यक है। संहिता की धारा 376 और 307 इस प्रकार है:

ग

“306. सहयोगी को क्षमा का प्रस्ताव।-(1) की दृष्टि से

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट, अपराध की जांच या जांच या मुकदमे के किसी भी स्तर पर, और प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट, जांच या मुकदमे के किसी भी स्तर पर, ऐसे व्यक्ति को अपराध के संबंध में अपनी जानकारी में पूरी परिस्थितियों का पूर्ण और सही खुलासा करने की शर्त पर और प्रत्येक अन्य संबंधित व्यक्ति को, चाहे वह प्रधान या सहायक के रूप में, अपराध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित या गुप्त होने का साक्ष्य प्राप्त कर सकता है।

डी.

ई.

(2) यह धारा लागू होती है-(क) विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा या आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1952 (1952 का 46) के तहत नियुक्त विशेष न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा विचारण योग्य कोई अपराध (ख) कारावास से दंडनीय कोई अपराध जो सात साल तक या अधिक गंभीर सजा से हो सकता है।(3) प्रत्येक मजिस्ट्रेट जो उप-धारा (1) के तहत माफी देता है, वह दर्ज करेगा -

च

जी.

((क) ऐसा करने के उसके कारण;

(ख) क्या निविदा उस व्यक्ति द्वारा स्वीकार की गई थी या नहीं जिसे वह दी गई थी,

एच.

14 (2016) 11 एससीसी 733 ए

47

ए. श्रीनिवासुलु बनाम राज्य प्रतिनिधि. पुलिस निरीक्षक द्वारा [वी. रामसुब्रमणियन, जे.] ए.

और अभियुक्त द्वारा किए गए आवेदन पर, उसे ऐसे अभिलेख की एक प्रति निःशुल्क प्रदान करेगा।

(4) उप-धारा (1) के तहत की गई क्षमा की निविदा स्वीकार करने वाला प्रत्येक व्यक्ति -

(क) अपराध का संज्ञान लेते हुए मजिस्ट्रेट के न्यायालय में गवाह के रूप में पूछताछ की जाएगी और बाद के मुकदमे में, यदि कोई हो,

(ख) जब तक वह पहले से ही जमानत पर नहीं है, तब तक उसे मुकदमे की समाप्ति तक हिरासत में रखा जाएगा।

(5) जहां किसी व्यक्ति ने उप-धारा (1) के तहत की गई क्षमा की निविदा स्वीकार कर ली है और उप-धारा (4) के तहत उसकी जांच की गई है, तो अपराध का संज्ञान लेते हुए मजिस्ट्रेट मामले में आगे कोई जांच किए बिना,

ग

(क) इसे विचारण के लिए प्रस्तुत करें-(i) सत्र न्यायालय को यदि अपराध विशेष रूप से उस न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है या यदि संज्ञान लेने वाला मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है;

डी.

((ख) आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, 1952 (1952 का 46) के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश के न्यायालय को, यदि अपराध विशेष रूप से उस न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है;

ई.

(ख) किसी अन्य मामले में, मामले को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सौंप दें जो स्वयं मामले की सुनवाई करेंगे।

307. क्षमा की निविदा का निर्देश देने की शक्ति।—इसके बाद किसी भी समय

च

किसी मामले की प्रतिबद्धता लेकिन निर्णय पारित होने से पहले, जिस न्यायालय के लिए प्रतिबद्धता की जाती है, वह मुकदमे में किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से, जिसके बारे में माना जाता है कि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे किसी अपराध से संबंधित था या उससे संबंधित था, ऐसे व्यक्ति को उसी शर्त पर माफी दे सकता है।"

जी.

60. पी. सी. अधिनियम की धारा 5 इस प्रकार है:

"5. विशेष न्यायाधीश की प्रक्रिया और शक्तियाँ।—(1) एक विशेष

न्यायाधीश अभियुक्त पर मुकदमा चलाए बिना ही अपराधों का संज्ञान ले सकता है और अभियुक्त व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने में मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों के मुकदमे के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा।

एच.

48

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

(2) एक विशेष न्यायाधीश, किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से, जिसके बारे में माना जाता है कि वह किसी अपराध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित था, या उससे संबंधित था, अपराध से संबंधित अपनी जानकारी में पूरी परिस्थितियों का पूरा और सही खुलासा करने की शर्त पर ऐसे व्यक्ति को और प्रत्येक अन्य संबंधित व्यक्ति को, चाहे वह प्रधान या सहायक के रूप में हो, इसके आयोग में क्षमा कर सकता है और इस तरह से दी गई कोई भी क्षमा, दंड प्रक्रिया संहिता,

1973 (1974 का 2) की धारा 308 की उप-धारा (1) से (5) के प्रयोजनों के लिए, उस संहिता की धारा 307 के तहत दी गई मानी जाएगी।

(3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के प्रावधान, जहां तक वे इस अधिनियम से असंगत नहीं हैं, एक विशेष न्यायाधीश के समक्ष की कार्यवाही पर लागू होंगे और उक्त प्रावधानों के प्रयोजनों के लिए, विशेष न्यायाधीश का न्यायालय सत्र न्यायालय माना जाएगा और एक विशेष न्यायाधीश के समक्ष अभियोजन करने वाले व्यक्ति को लोक अभियोजक माना जाएगा। (4) विशेष रूप से और उप-धारा (3) में निहित प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 326 और 475 के प्रावधान, जहां तक हो सके, विशेष न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही पर लागू होंगे और उक्त प्रावधानों के प्रयोजनों के लिए, एक विशेष न्यायाधीश को मजिस्ट्रेट माना जाएगा।

ग

डी.

ई.

(5) एक विशेष न्यायाधीश अपने द्वारा दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को उस अपराध की सजा के लिए कानून द्वारा अधिकृत कोई भी सजा दे सकता है जिसके लिए ऐसा व्यक्ति दोषी ठहराया जाता है।

च

(6) एक विशेष न्यायाधीश, इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध की सुनवाई करते समय, आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश, 1944 (1944 का अध्यादेश 38) के तहत एक जिला न्यायाधीश द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करेगा।"

61. संहिता की धारा 306 की शरीर रचना पर सावधानीपूर्वक नज़र डालने से पता चलता है कि यह वैकल्पिक या अतिरिक्त रूप से कई कदम प्रदान करता है। वे इस प्रकार हैं:- -प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

जी.

(i) धारा 376 (1) एक आपराधिक मामले को तीन चरणों में विभाजित करती है, अर्थात् (i) जांच; (ii) जांच; और (iii) अपराध का मुकदमा।

एच.

49

ए. श्रीनिवासुलु बनाम राज्य प्रतिनिधि. पुलिस निरीक्षक द्वारा [वी. रामसुब्रमणियन, जे.] ए.

क.

((ii) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को किसी भी व्यक्ति को तीन चरणों में से किसी भी चरण, अर्थात् जांच के चरण, जांच के चरण या मुकदमे के चरण में माफी देने का अधिकार है। इसके विपरीत, प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट केवल दो चरणों में माफी दे सकता है, अर्थात् अपराध की जांच का चरण या मुकदमा चलाने का चरण।

(iii) धारा 306 की उप-धारा (2) धारा 306 के प्रावधानों को आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1952 के तहत नियुक्त सत्र न्यायालय या विशेष न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा विशेष रूप से विचारणीय किसी भी अपराध पर और कारावास से दंडनीय किसी भी अपराध पर लागू करती है जो सात साल या उससे अधिक तक हो सकता है।

ग

(iv) धारा 376 की उप-धारा (3) मजिस्ट्रेट को माफी देने के लिए बाध्य करती है, न केवल ऐसा करने के कारणों को दर्ज करने के लिए बल्कि यह भी बताने के लिए कि क्या निविदा उस व्यक्ति द्वारा स्वीकार की गई थी जिसे वह दी गई थी।

डी.

(v) धारा 306 की उप-धारा (4) यह अनिवार्य बनाती है कि उप-धारा (1) के तहत की गई क्षमा की निविदा स्वीकार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से मजिस्ट्रेट के न्यायालय में संज्ञान लेते हुए और बाद के मुकदमे में गवाह के रूप में पूछताछ की जाएगी। उप-धारा (4) एक अतिरिक्त शर्त भी लगाती है कि क्षमा की निविदा स्वीकार करने वाले व्यक्ति को मुकदमे की समाप्ति तक हिरासत में रखा जाएगा, सिवाय इसके कि जब वह पहले से ही जमानत पर हो।

ई.

(vi) उप-धारा (4) के खंड (ए) और (बी) पर सावधानीपूर्वक नज़र डालने से पता चलता है कि उसमें निर्धारित प्रक्रिया केवल उप-धारा (1) द्वारा कवर किए गए मामलों पर लागू होती है।

च

(vii) उप-धारा (5) में यह विहित किया गया है कि एक बार जब कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के तहत क्षमा की निविदा स्वीकार कर लेता है और उप-धारा (4) के तहत उसकी जांच की जाती है, तो मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेते हुए मामले को सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय या विशेष न्यायाधीश के न्यायालय को सौंप देना चाहिए। उप-धारा (5) के खंड (ए) के दायरे में नहीं आने वाले मामलों में, मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेते हुए खंड (बी) के संदर्भ में मामले को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सौंपना चाहिए।

जी.

एच.

50

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

62. संहिता की धारा 307 उस न्यायालय को क्षमा करने का अधिकार देती है जिसके प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की जाती है। मामले की प्रतिबद्धता के बाद लेकिन निर्णय पारित होने से पहले किसी भी समय शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। 63. पी. सी. अधिनियम की धारा 5 पर आते हुए, यह देखा गया है कि उप-धारा (1) विशेष न्यायाधीश को अभियुक्त को मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध किए बिना अपराधों का संज्ञान लेने का अधिकार देती है। इसमें यह भी कहा गया है कि अभियुक्त व्यक्तियों पर मुकदमा चलाते समय, विशेष न्यायाधीश मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों की सुनवाई के लिए संहिता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य है। यही कारण है कि इस अदालत ने बंगारू लक्ष्मण (पैरा में) में फैसला सुनाया।

40 रिपोर्ट) कि पी. सी. अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश को अपराधों की सुनवाई करते समय सत्र न्यायाधीश के साथ-साथ मजिस्ट्रेट की दोहरी शक्ति है और यह कि ऐसा विशेष न्यायाधीश आरोप पत्र दाखिल करने से पहले और दोनों के लिए कार्यवाही करता है।

ग

मुकदमा चलाना। वास्तव में बंगारू लक्ष्मण में सवाल यह था कि आरोप पत्र दाखिल करने से एक दिन पहले विशेष न्यायाधीश द्वारा दी गई माफी सही थी या नहीं। इस अदालत ने वही क्रम में पाया।

डी.

64. दिलचस्प बात यह है कि धारा 5 की उप-धारा (2) जो विशेष न्यायाधीश को माफी देने का अधिकार देती है, उस चरण के बारे में नहीं बताती है जिस पर एक विशेष न्यायाधीश माफी दे सकता है। इस बात की सराहना की जा सकती है यदि हम एक बार

फिर संहिता की धाराओं, जो निम्नलिखित नियमों को निर्धारित करती हैं, पर वापस जाएँ:- -प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ई.

(i) एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या एक महानगर मजिस्ट्रेट को तीन चरणों में से किसी भी चरण में माफी देने का अधिकार है; **(ii)** प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को दो चरणों में माफी देने का अधिकार है; और

च

(ग) वह न्यायालय जिसके प्रति वचनबद्धता की जाती है (जिसका अर्थ है कि या तो सत्र न्यायालय या धारा 206 की उप-धारा (5) के खंड (क) के उपखंड (i) और (ii) में नामित विशेष न्यायाधीश का न्यायालय) केवल एक चरण में क्षमा करने के लिए सशक्त है, अर्थात् अपराध का विचारण। यद्यपि धारा 305 (1) में प्रयुक्त परीक्षण शब्द का उपयोग धारा 307 में नहीं किया गया है, लेकिन धारा 307 में आने वाले शब्द, अर्थात् "किसी भी समय बाद में", का उपयोग किया गया है।

जी.

एक मामले की प्रतिबद्धता लेकिन निर्णय पारित होने से पहले "

केवल मुकदमे के चरण का संकेत दे सकते हैं, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि धारा 376 की उप-धारा (5) के तहत, अपराध को संज्ञान लेने के बाद किया जाता है।

एच.

51

ए. श्रीनिवासुलु बनाम राज्य प्रतिनिधि. पुलिस निरीक्षक द्वारा [वी. रामसुब्रमणियन, जे.] ए.

क.

65. इसके विपरीत, पी. सी. अधिनियम की धारा 5 (2) उस चरण के बारे में नहीं बताती है जिस पर एक विशेष न्यायाधीश द्वारा माफी दी जा सकती है। यह संभवतः धारा 5 की उप-धारा (1) के स्पष्ट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए है जो विशेष न्यायाधीश को स्वयं अभियुक्त को मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध किए बिना संज्ञान लेने का अधिकार देता है। लेकिन पी. सी. अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) का दूसरा भाग एक काल्पनिक कल्पना पैदा करता है कि विशेष न्यायाधीश द्वारा दी गई माफी को संहिता की धारा 307 के तहत दी गई माफी माना जाएगा। हालाँकि, जैसा कि ए-7 के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा सही तर्क दिया गया है, यह काल्पनिक धारणा संहिता की धारा 308 की उप-धारा (1) से (5) के उद्देश्यों के लिए सीमित है।

66. ऐसा प्रतीत होता है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के आने से पहले, न्यायालयों का विचार था कि मजिस्ट्रेटों के पास सत्र न्यायालय/विशेष न्यायाधीश को मुकदमे के लिए मामले की प्रतिबद्धता के बाद भी माफी देने की शक्ति थी। इसका कारण यह था कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 338 को जिस तरह से लिखा गया था। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 307 की तुलना दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 338 से स्थिति और अधिक स्पष्ट हो जाएगी।

ग

डी.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 307	दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 338
307. क्षमा की निविदा का निर्देश देने की शक्ति। —	338. क्षमा की निविदा का निर्देश देने की शक्ति। -

किसी मामले की प्रतिबद्धता के बाद किसी भी समय, लेकिन निर्णय पारित होने से पहले, जिस न्यायालय को प्रतिबद्धता दी जाती है, वह मुकदमे में किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से, जिसके बारे में माना जाता है कि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे अपराध से संबंधित था या उससे संबंधित था, ऐसे व्यक्ति को उसी शर्त पर क्षमा कर सकता है।	प्रतिबद्धता के बाद किसी भी समय, लेकिन निर्णय पारित होने से पहले, जिस न्यायालय को प्रतिबद्धता दी जाती है, वह मुकदमे में किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से, जिसके बारे में माना जाता है कि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे अपराध में संबंधित था, या उससे संबंधित था, समर्पण कर सकता है, या समर्पण करने वाले मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उसी शर्त पर माफी देने का आदेश दे सकता है।
---	--

ई.

च

जी.

67. विधानमंडल द्वारा 1973 की संहिता की धारा 376 और 307 में निर्धारित प्रक्रिया में लाए गए परिवर्तन को इस न्यायालय द्वारा ए. देवेंद्रन बनाम में नोट किया गया था। राज्य टी. एन. 15. संयोग से, ए. देवेंद्रन (ऊपर) में एक सवाल उठा कि क्या परीक्षा का गैर-परीक्षण

15 (1997) 11 एससीसी 720

एच.

52

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

क्षमा प्रदान किए जाने के बाद एक गवाह के रूप में अनुमोदन धारा 376 की उप-धारा (4) (ए) का गैर-अनुपालन था और क्या यह कार्यवाही को दूषित करेगा। A.Devendran में निर्णय का पैराग्राफ 10 महत्वपूर्ण है और इसलिए इसे निम्नानुसार निकाला गया है:- प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“10. अगला प्रश्न जो विचार के लिए उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या क्षमा प्रदान करने के बाद गवाह के रूप में सरकारी गवाह से पूछताछ न करना और इस तरह धारा 376 की उप-धारा 4 (ए) का पालन न करना पूरी कार्यवाही को दूषित करता है। मामले में

हाथ में इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को क्षमा देने के तुरंत बाद उसकी जाँच नहीं की गई थी और मुकदमे के दौरान विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा केवल एक बार उसकी जाँच की गई थी। विचार के लिए जो प्रश्न उत्पन्न होता है वह है: जब मामला सत्र न्यायालय को सौंपे जाने के बाद किसी अभियुक्त को क्षमा दी जाती है तो क्या संहिता की धारा 376 की उप-धारा (4) (ए) का पालन करना आवश्यक होगा। इस संबंध में राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री मोहन का तर्क है कि धारा 307 केवल यह आदेश देती है कि माफी उसी शर्त पर दी जानी चाहिए और ऐसी शर्त स्पष्ट रूप से धारा 306 की उप-धारा (1) में दर्शाई गई शर्त को संदर्भित करती है, अर्थात्, अभियुक्त द्वारा अपराध से संबंधित अपनी जानकारी में पूरी परिस्थितियों का पूर्ण और सही खुलासा करने पर और प्रत्येक अन्य संबंधित व्यक्ति को, चाहे वह प्रधान या सहायक के रूप में हो। विद्वान वकील के अनुसार, धारा 306 की उप-धारा (4) माफी देने के लिए एक शर्त नहीं है, बल्कि केवल एक प्रक्रिया है जिसका पालन तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति को धारा 306 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए मजिस्ट्रेट द्वारा माफी दी जाती है। चूंकि सत्र न्यायालय को किए गए किसी मामले में उस न्यायालय द्वारा माफी दिए जाने के बाद, जिसके लिए प्रतिबद्धता की गई है, ऐसे न्यायालय के लिए धारा 376 की उप-धारा (4) (ए) का पालन करना आवश्यक नहीं होगा।

ग

डी.

ई.

च

दूसरी ओर, अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान वकील श्री मुरलीधर ने तर्क दिया कि धारा 376 की उप-धारा (4) के खंड (ए) में निहित उद्देश्य और उद्देश्य अभियुक्त को सुरक्षा प्रदान करना है जो प्रारंभिक स्तर पर भी प्रतिपरीक्षा कर सकता है।

जी.

उसके खिलाफ सरकारी गवाह का साक्ष्य और उक्त गवाही पर महाभियोग चला सकता है जब सरकारी गवाह से मुकदमे के दौरान अदालत में पूछताछ की जाती है, यदि उसके द्वारा कोई विरोधाभास या सुधार किए जाते हैं। अभियुक्त के इस अधिकार से उसे केवल इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता है क्योंकि ए

एच.

53

ए. श्रीनिवासुलु बनाम राज्य प्रतिनिधि. पुलिस निरीक्षक द्वारा [वी. रामसुब्रमणियन, जे.] ए.

सत्र न्यायालय में कार्यवाही किए जाने के बाद माफी दी जाती है।

68. जैसा कि ऊपर से देखा गया है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उस मामले में आरोपी को माफी दे दी, लेकिन माफी देने के तुरंत बाद उससे पूछताछ नहीं की गई और मुकदमे के दौरान सत्र न्यायाधीश के समक्ष केवल एक बार उससे पूछताछ की गई। इसलिए, जो प्रश्न उत्पन्न हुआ वह यह था कि क्या धारा 306 की उप-धारा (4) (ए) का पालन करना आवश्यक था, जब किसी अभियुक्त को मामला सत्र न्यायालय को सौंपे जाने के बाद माफी दी जाती है। जैसा कि ए. देवेन्द्रन में इस न्यायालय के समक्ष दिए गए तर्क से देखा जा सकता है कि धारा 306 की उप-धारा (4) के खंड (ए) का उद्देश्य अभियुक्त को सुरक्षा प्रदान करना है ताकि वह सरकारी गवाह के साक्ष्य को जानने पर प्रारंभिक चरण में भी प्रतिपरीक्षा कर सके और जब अदालत में सरकारी गवाह से मुकदमे के दौरान पूछताछ की जाए तो उक्त गवाही पर महाभियोग चला सके।

69. उक्त प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए, ए. देवेंद्रन के मामले में न्यायालय ने पहले एक ऐसे मामले के बीच अंतर किया जहां सत्र न्यायालय को उसी की प्रतिबद्धता से पहले माफी की निविदा दी गई थी और एक ऐसे मामले के बीच जहां प्रतिबद्धता के बाद माफी दी जाती है। इस तरह का अंतर करने के बाद, इस आधार पर कि क्या समर्पण से पहले या बाद में माफी दी गई थी, इस न्यायालय ने देवेंद्रन (पैरा 11) में निम्नानुसार निर्णय दिया:- -प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

ई.

“11. ... धारा 376 और धारा 307 की उप-धारा (4) के संयुक्त अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि किसी मामले में विशेष रूप से

सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य यदि किसी अभियुक्त को क्षमा प्रदान की जाती है और उसे प्रतिबद्धता से पहले सरकारी गवाह के रूप में लिया जाता है तो धारा 376 की उप-धारा (4) का अनुपालन अनिवार्य हो जाता है और ऐसी अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन न करने से कार्यवाही दूषित हो जाएगी, लेकिन यदि कोई अभियुक्त

च

न्यायालय द्वारा प्रतिबद्धता के बाद क्षमा की जाती है, जिसके लिए धारा 307 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यवाही की जाती है, तो ऐसे मामले में धारा 306 की उप-धारा (4) के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं।...”

जी.

70. उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, इस न्यायालय ने अपने

सुरेश चंद्र बहरी बनाम बिहार राज्य 16 में पिछला निर्णय,

जिसमें यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था:- -प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

16 1995 पूरक (1) एस. सी. सी. 80

एच.

54

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

“30. संहिता की धारा 376 की उप-धारा (4) के खंड (ए) को केवल पढ़ने से यह पता चलेगा कि उप-धारा (1) के तहत की गई क्षमा की निविदा को स्वीकार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से अपराध का संज्ञान लेते हुए मजिस्ट्रेट के न्यायालय में गवाह के रूप में पूछताछ की जानी चाहिए और बाद के मुकदमे में, यदि कोई हो। उप-धारा (5) में आगे यह प्रावधान है कि अपराध का संज्ञान लेते हुए मजिस्ट्रेट मामले में कोई और जांच किए बिना, यथास्थिति, उप-धारा (5) के खंड (ए) के खंड (i) या (ii) में उल्लिखित न्यायालयों में से किसी एक को मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध करेगा। संहिता की धारा 209 सत्र न्यायालय के प्रति मामलों की प्रतिबद्धता से संबंधित है जब अपराध की सुनवाई विशेष रूप से उस न्यायालय द्वारा की जाती है। द.

अपराध का संज्ञान लेते हुए मजिस्ट्रेट के न्यायालय में गवाह के रूप में क्षमा की निविदा को स्वीकार करने के बाद साथी या सरकारी गवाह की जांच इस प्रकार एक अनिवार्य प्रावधान है और इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है और यदि इस अनिवार्य प्रावधान का पालन नहीं किया जाता है तो यह मुकदमे को दूषित कर देता है। जैसा कि परिकल्पना की गई थी

ग

धारा 306 की उप-धारा (1) में, क्षमा की निविदा इस शर्त पर दी जाती है कि एक अनुमोदनकर्ता अपराध से संबंधित अपनी जानकारी के भीतर पूरी परिस्थितियों का पूर्ण और सही खुलासा करेगा। नतीजतन, जांच करने में विफलता

डी.

अपराध करने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष गवाह के रूप में अनुमोदक न केवल धारा 376 की उप-धारा (4) के खंड (ए) में निहित अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, बल्कि यह सभी चरणों में मामले का पूर्ण और स्पष्ट खुलासा करने के कर्तव्य के साथ असंगत और उल्लंघन भी होगा। धारा 376 की उप-धारा (4) के खंड (ए) में निहित प्रावधानों का उल्लंघन अनिवार्य प्रकृति का है और केवल निर्देशिका नहीं है और इसलिए, इसका पालन न करने से प्रतिबद्ध आदेश अवैध हो जाएगा। उद्देश्य और उद्देश्य

ई.

च

इस अनिवार्य प्रावधान को लागू करने में स्पष्ट रूप से अभियुक्त को सुरक्षा प्रदान करने का इरादा है क्योंकि सरकारी गवाह को न्यायिक आदेश दिए जाने से पहले प्रारंभिक चरण में अपने साक्ष्य का खुलासा करते हुए एक बयान देना होता है और आरोपी को न केवल उसके खिलाफ साक्ष्य के बारे में पता चलता है, बल्कि उसे न्यायिक गवाह से मिलने का अवसर भी दिया जाता है ताकि वह यह दिखाने के लिए कदम उठा सके कि मुकदमे में सरकारी गवाह का साक्ष्य अविश्वसनीय था यदि मुकदमे में उसके द्वारा अपने साक्ष्य के दौरान कोई विरोधाभास या सुधार किए गए थे। यही कारण है कि ए

जी.

एच.

55

ए. श्रीनिवासुलु बनाम राज्य प्रतिनिधि. पुलिस निरीक्षक द्वारा [वी. रामसुब्रमणियन, जे.] ए.

कि दो चरणों में अनुमोदक की जांच का प्रावधान किया गया है और यदि उक्त अनिवार्य प्रावधान का पालन नहीं किया जाता है, तो अभियुक्त उक्त लाभ से वंचित हो जाएगा। यह उसके लिए गंभीर पूर्वाग्रह का कारण बन सकता है जिसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हो सकती है क्योंकि वह सरकारी गवाह के साक्ष्य को अविश्वसनीय के रूप में दिखाने का अवसर खो देगा। संहिता की धारा 376 की उप-धारा (4) के आगे खंड (बी) से यह भी पता चलेगा कि यह आदेश देता है कि एक व्यक्ति जिसने क्षमा की निविदा स्वीकार कर ली है, उसे तब तक हिरासत में रखा जाएगा जब तक कि वह पहले से ही जमानत पर न हो। हमारे पास है,

इसलिए, यह भी देखने के लिए कि क्या तत्काल मामले में इन दो अनिवार्य प्रावधानों का पालन किया गया था या नहीं और यदि उनका पालन नहीं किया गया था, तो मुकदमे पर इस तरह के गैर-अनुपालन का क्या प्रभाव पड़ता है?"

ग

71. यह देखना दिलचस्प है कि सुरेश चंद्र बहरी के मामले में, इस अदालत ने पहले यह निर्णय दिया कि संहिता की धारा 376 (4) (ए) में निर्धारित प्रक्रिया अनिवार्य है और निर्देशिका नहीं है और इसका पालन न करने से समर्पण आदेश अवैध हो जाएगा। इस तरह के निर्णय के बाद, इस अदालत ने ऊपर निकाले गए पैरा 30 की अंतिम पंक्ति में एक सवाल उठाया कि मुकदमे पर इस तरह के गैर-अनुपालन का क्या प्रभाव पड़ता है। इस सवाल का जवाब देते हुए, इस अदालत ने सुरेश चंद्र बहरी में पाया कि जिस

अदालत में मामला किया गया था, उसने इस अनियमितता को सीमा पर भी देखा और इसलिए मामले को सरकारी गवाह की गवाही दर्ज करने के लिए मजिस्ट्रेट को वापस भेज दिया। इस प्रकार दोष मुकदमे से पहले ठीक हो गया और इसलिए इस अदालत ने निर्णय के पैराग्राफ 31 में कहा कि अंततः कोई पूर्वाग्रह नहीं है।

डी.

ई.

या अभियुक्त को नुकसान पहुँचाया गया था।

72. इस प्रकार, सुरेश चंद्र बहरी में दो विशिष्ट विशेषताएं थीं। पहला यह था कि उस मामले में माफी देने वाले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अदालत में गवाह के रूप में सरकारी गवाह की जांच किए बिना मामले को सुनवाई के लिए (मामले के विपरीत) सत्र न्यायालय को सौंप दिया। दूसरी विशिष्टता यह थी कि जिस न्यायालय को मुकदमा चलाने के लिए मामला सौंपा गया था, उसने दोष को देखा और इसलिए मामले को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में वापस भेज दिया। इसलिए, इस अदालत ने उस मामले में पूर्वाग्रह परीक्षण लागू किया।

च

जी.

73. लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सुरेश चंद्र बहरी में जो दूषित करने के लिए आयोजित किया गया था, वह प्रतिबद्ध आदेश था। इसलिए यह कहा गया

अंततः सुरेश चंद्र बहरी में यह निष्कर्ष निकाला गया कि जिस क्षण अभियोग आदेश में दोष परीक्षण से पहले ठीक हो जाता है, परीक्षण दूषित नहीं होता है।

एच.

56

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

74. लेकिन ऐसे मामलों में जहां एक विशेष न्यायालय स्वयं संज्ञान लेने के लिए सक्षम है और माफी देने के लिए भी सशक्त है, संहिता की धारा 376 के तहत प्रक्रिया को पारित कर दिया जाता है, जैसा कि राज्य में इस न्यायालय ने सीबीआई बनाम वी. अरुल कुमार 17 के माध्यम से अभिनिर्धारित किया है। अरुल में एक तर्क दिया गया था

कुमार (ऊपर) (जैसा कि रिपोर्ट के पैराग्राफ 20 से देखा गया है) कि धारा

306 पी. सी. अधिनियम के तहत अपराधों से संबंधित मामलों में संहिता का कोई अनुप्रयोग नहीं है। उक्त तर्क के समर्थन में, पी. सी. मिश्रा बनाम में निर्णय। राज्य (सी. बी. आई.) 18 पर भी भरोसा किया गया। उक्त विवाद पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने अरुल कुमार के मामले में निम्नलिखित निर्णय दिया:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“21. धारा 5 की उप-धारा (1), जबकि एक विशेष न्यायाधीश को अभियुक्त को मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध किए बिना अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार देती है, केवल संहिता की धारा 193 की अन्यथा अनिवार्य आवश्यकता को माफ करने का प्रभाव डालती है। संहिता की धारा 193 में कहा गया है कि सत्र न्यायालय मूल अधिकार क्षेत्र के न्यायालय के रूप में किसी भी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं ले सकता जब तक कि संहिता के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा मामला नहीं किया गया हो। इस प्रकार, संहिता की धारा 193 का प्रतिबंध हटा लिया गया है। हालाँकि, इसमें कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। इस प्रकार, विशेष न्यायाधीश को एक विकल्प दिया गया है कि वह सीधे अपराधों का संज्ञान ले और मजिस्ट्रेट के माध्यम से अपराध को अंजाम देने का रास्ता न अपनाए। हालाँकि, संहिता की धारा 190 के तहत निर्धारित सामान्य प्रक्रिया,

जो मजिस्ट्रेट को ऐसे अपराधों का संज्ञान लेने के लिए सशक्त बनाती है, हालांकि सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, को मंजूरी नहीं दी जाती है। दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। उन मामलों में जहां मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप पत्र दायर किया जाता है, उसे इसे विशेष न्यायाधीश को सौंपना होगा। इस स्थिति में संहिता की धारा 306 के प्रावधान लागू होंगे और मजिस्ट्रेट को उक्त प्रावधान के तहत शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार होगा। इसके विपरीत, उन मामलों में जहां विशेष न्यायाधीश सीधे अपराध का संज्ञान लेते हैं, क्योंकि वे पी. सी. अधिनियम, 1988 की धारा 5 (2) को देखते हुए ऐसा करने के लिए अधिकृत हैं, संहिता की धारा 376 को दरकिनार कर दिया जाएगा और जैसा कि विशेष न्यायाधीश ने संज्ञान लिया है, यह संहिता की धारा 307 है जो लागू होगी। पी. सी. अधिनियम, 1988 की धारा 5 की उप-धारा (2) इस स्थिति को यह निर्धारित करके स्पष्ट करती है कि यह विशेष न्यायाधीश है जो इसका प्रयोग करेगा।

ग

डी.

ई.

च

जी.

17 (2016) 11 एससीसी 733 18 (2014) 14 एससीसी 629 ए

एच.

57

ए. श्रीनिवासुलु बनाम राज्य प्रतिनिधि. पुलिस निरीक्षक द्वारा [वी. रामसुब्रमणियन, जे.] ए.

क्षमा करने की उसकी शक्तियों को उस प्रावधान में प्रयुक्त भाषा द्वारा स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। धारा 5 (2) को पी. सी. अधिनियम, 1988 की धारा 5 (1) के साथ पढ़ा जाना है। उपरोक्त कानूनी स्थिति इस निर्णय के आधार पर प्रतिवादी के विद्वान वकील के तर्क का भी जवाब देगी।

ए. देवेंद्रन [ए. देवेंद्रन बनाम टी. एन. राज्य, (1997)]

11 एससीसी 720:1998 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 220] उस मामले में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक बार कार्यवाही सत्र न्यायालय के लिए प्रतिबद्ध हो जाने के बाद, यह केवल वह न्यायालय है जिसके लिए प्रतिबद्धता की जाती है जो सरकारी गवाह को क्षमा प्रदान कर सकता है। बल्कि, हमारे द्वारा लिया गया दृष्टिकोण उक्त निर्णय के अनुरूप है।"

ग

75. दूसरे शब्दों में, इस न्यायालय ने अरुल कुमार में दो प्रकार के मामलों को मान्यता दी, अर्थात् (i) वे जो प्रतिबद्ध मार्ग से आते हैं; और (ii) वे जहां पी. सी. अधिनियम की धारा 5 (1) के तहत विशेष न्यायाधीश द्वारा सीधे संज्ञान लिया जाता है। मामलों की दूसरी श्रेणी में, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संहिता की धारा 376 को पारित कर दिया जाएगा।

डी.

76. इसलिए, यह स्पष्ट है कि जब विशेष न्यायालय संज्ञान लेने का विकल्प चुनता है, तो धारा 376 (4) (ए) द्वारा आवश्यक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में गवाह के रूप में सरकारी गवाह से पूछताछ का सवाल नहीं उठता है। इसलिए प्रत्यर्थी के विद्वान वकील श्री पद्मेश मिश्रा ने सरदार मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा करना सही है।

इकबाल सिंह बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) 19 और याकूब अब्दुल रजाक मेमन बनाम महाराष्ट्र राज्य 20

ई.

77. सरदार इकबाल सिंह (ऊपर) में अपराध की सुनवाई विशेष न्यायाधीश द्वारा की गई थी, जिन्होंने भी संज्ञान लिया था। इसलिए, कोई समर्पण कार्यवाही नहीं हुई। यद्यपि सरदार इकबाल सिंह का उदय 1898 की संहिता के तहत हुआ था, 1898 की संहिता की धारा 337 की उप-धारा (2) 1973 की संहिता की धारा 376 (4) (ए) के समान थी। इसलिए, सरदार इकबाल सिंह में निर्धारित अनुपात को याकूब अब्दुल रजाक मेमन (उपरोक्त) में इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सही ढंग से लागू किया गया था कि जहां एक विशेष न्यायाधीश मामले का संज्ञान लेता है, तो गवाह के रूप में सरकारी गवाह से पूछताछ करने का अवसर केवल एक बार आता है।

च

जी.

78. किसी भी मामले में, अब तक उद्धृत सभी निर्णय, समान रूप से कहते हैं कि एक सरकारी गवाह से दो बार पूछताछ करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरोपी को प्रारंभिक चरण में भी उसके खिलाफ साक्ष्य से अवगत कराया जाए।

19 (1977) 4 एससीसी 536 20 (2013) 13 एससीसी 1

एच.

58

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

ताकि वह मुकदमे के दौरान सरकारी गवाह से प्रभावी ढंग से जिरह कर सके, विरोधाभासों को सामने ला सके और उसे अविश्वसनीय दिखा सके। उक्त उद्देश्य इस मामले में पूरा हो गया है, क्योंकि XVIII मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष सरकारी गवाह का स्वीकारोक्ति बयान आरोप पत्र के साथ संलग्न था। मुकदमे के दौरान सरकारी गवाह से पीडब्लू-16 के रूप में पूछताछ की गई और स्वीकारोक्ति बयान की सामग्री पर उससे जिरह की गई। स्वीकारोक्ति दर्ज करने वाले मजिस्ट्रेट से पीडब्लू 17 के रूप में पूछताछ की गई और माफी देने वाले अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से पीडब्लू-18 के रूप में पूछताछ की गई। XVIII मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही, संहिता की धारा 376 के तहत याचिका और माफी के निविदा पर कार्यवाही को क्रमशः EXX के रूप में चिह्नित किया गया था। पी-50,51 और 52। सभी अभियुक्तों को प्रक्रिया और विषय-वस्तु दोनों पर इन गवाहों से जिरह करने का अवसर दिया गया था।

ग

79. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि संहिता की धारा 376 (4) (ए) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था। इस प्रकार, हम अपीलार्थियों के खिलाफ दूसरे मुद्दे का जवाब देते हैं।

डी.

भाग-III (हमारे समक्ष प्रत्येक अपीलार्थी की दोषसिद्धि के मामले के गुण-दोष के इर्द-गिर्द घूमना)

ए-1 के बारे में

80. हालाँकि हमने इस निर्णय के भाग-1 में पाया है कि संहिता की धारा 197 (1) के तहत पूर्व मंजूरी लेने में अभियोजन पक्ष की विफलता ने ए-1 के खिलाफ कार्यवाही को दूषित कर दिया है, फिर भी हम यह देखने के लिए गुण-दोष के आधार पर उनके मामले पर विचार करेंगे कि क्या आईपीसी या पी. सी. अधिनियम के तहत अपराध उचित संदेह से परे साबित हुए हैं। 81. पुनर्कथन के लिए, ए-1 के खिलाफ आरोप हैं (i) बी. एच. ई. एल. को धोखा देने और ए-5 की फर्म को निविदा देने के लिए एक आपराधिक साजिश में प्रवेश करके और पी. डब्ल्यू-16 को संभावित निविदाकारों की पूर्व-योग्यता की प्रक्रिया का पालन किए बिना और ठेकेदारों की अनुमोदित सूची में से किसी का चयन किए बिना सीमित निविदाओं के लिए जाने का निर्देश देकर, उसने

आई. पी. सी. के तहत दंडनीय विभिन्न अपराध किए; और (ii) अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके और ए-5 को अनुबंध देकर, उसने 5 करोड़ रुपये का गलत नुकसान किया। बी. एच. ई. एल. को 4 करोड़ 32 लाख रुपये।

ई.

च

जी.

82. आपराधिक साजिश के संबंध में आरोपों को साबित करने और यह स्थापित करने के लिए कि ए-1 ने एक चुनी हुई फर्म को अनुबंध देने के उद्देश्य से प्रतिबंधित निविदा के लिए जाने का फैसला किया और यह भी दिखाने के लिए कि ए-1 ने चार फर्जी फर्मों को शामिल करने का निर्देश दिया, ए

एच.

59

ए. श्रीनिवासुलु बनाम राज्य प्रतिनिधि. पुलिस निरीक्षक द्वारा [वी. रामसुब्रमणियन, जे.] ए.

अभियोजन पक्ष ने अपने स्टार गवाह, अर्थात् पीडब्लू-16 पर भरोसा किया। लेकिन पी. डब्ल्यू.-16 एफ. आई. आर. में पहला नामित आरोपी था, जो बाद में स्वीकारोक्ति बयान देकर सरकारी गवाह बन गया।

83. जैसा कि विद्वान वरिष्ठ वकील श्री हुजेफा अहमदी ने सही तर्क दिया है, इस अदालत ने सरवन सिंह बनाम पंजाब राज्य 21 में दो परीक्षण निर्धारित किए हैं, जिन्हें एक सरकारी गवाह के साक्ष्य को स्वीकार करने से पहले संतुष्ट किया जाना चाहिए। पहला यह है कि सरकारी गवाह एक विश्वसनीय गवाह है और दूसरा यह है कि उसके बयान की पर्याप्त सबूतों के साथ पुष्टि की जानी चाहिए। पुनः, रविंदर सिंह बनाम हरियाणा राज्य 22 के मामले में इस न्यायालय ने कहा कि,

अनुमोदक एक सबसे अयोग्य मित्र है "और जिसके लिए उसने सौदेबाजी की है

उसकी प्रतिरक्षा, अदालत में विश्वसनीयता के लिए अपनी योग्यता साबित करनी चाहिए। पूरा किए जाने वाले परीक्षण को इस न्यायालय द्वारा रिपोर्ट के पैराग्राफ 12 में निम्नानुसार रखा गया था:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

"12. ... यह परीक्षा पूरी होती है, सबसे पहले, अगर वह जिस कहानी से संबंधित है वह उसे अपराध में शामिल करती है और आंतरिक रूप से उन घटनाओं की एक प्राकृतिक और संभावित सूची प्रतीत होती है जो हुई थीं। अगर कहानी को वास्तविकता के अनुसार संक्षिप्त विवरण दिया जाता है, तो यह संभावना है कि इसे अस्वीकार किए जाने से बचाया जा सकता है। दूसरा, एक बार उस बाधा को पार करने के बाद, जहां तक मुकदमे में आरोपी का संबंध है, एक सरकारी गवाह द्वारा दी गई कहानी में उसे इस तरह से फंसाया जाना चाहिए कि वह उचित संदेह से परे अपराध के निष्कर्ष को जन्म दे। एक दुर्लभ मामले में किसी विशेष मामले को नियंत्रित करने वाले सभी कारकों, परिस्थितियों और स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, एक सरकारी गवाह के अप्रमाणित साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि की अनुमति दी जा सकती है जिसे न्यायालय द्वारा विश्वासपूर्वक सच और विश्वसनीय माना जाता है। हालांकि, आम तौर पर, एक सरकारी गवाह के बयान की पुष्टि अपराध और अपराधी के बीच की दूरी को बारीकी से पाटने के लिए सामग्री विवरणों में की जानी चाहिए। यदि विश्वसनीय हो, तो अन्य स्वतंत्र विश्वसनीय साक्ष्यों की कसौटी से सीधे किसी अभियुक्त से संबंधित सरकारी गवाह द्वारा प्रकट की गई संलिप्तता की कुछ निर्णायक विशेषताएँ, उसकी गवाही की स्वीकृति के लिए आवश्यक आश्वासन देंगी, जिस पर दोषसिद्धि आधारित हो सकती है।"

डी.

ई.

च

जी.

84. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 133 एक साथी को एक सक्षम गवाह घोषित करती है और यह कि एक दोषसिद्धि केवल इसलिए अवैध नहीं है क्योंकि यह किसी व्यक्ति की अप्रमाणित गवाही पर आगे बढ़ती है।

21 1957 एससीआर 953 22 (1975) 3 एससीसी 742

एच.

60

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

सहयोगी। तथापि, धारा 133 के महत्व पर विचार करते हुए, यह

एम. ओ. शम्सुद्दीन बनाम में आयोजित न्यायालय। केरल राज्य **23** कि न्यायालय है

चित्रण में निहित एहतियाती प्रावधान पर ध्यान देने के लिए बाध्य

(ख) साक्ष्य अधिनियम की धारा **114**, जो यह प्रावधान करती है कि एक साथी श्रेय के योग्य नहीं है जब तक कि उसकी भौतिक विवरणों में पुष्टि नहीं की जाती है।

85. उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, यदि हम पीडब्लू-16 के साक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो यह देखा जाएगा कि वह अपनी त्वचा को बचाने के लिए ए-1 पर बोझ डालने की कोशिश कर रहा था। जिरह के दौरान उनके द्वारा की गई निम्नलिखित स्वीकारोक्ति से पता चला कि वह श्रेय के योग्य नहीं थे:- (i) 1994 तक बी. एच. ई. एल., त्रिची में रखे गए ठेकेदारों की कोई अनुमोदित सूची नहीं थी।

ग

((ii) यह कहना सही नहीं है कि 1994 तक बी. एच. ई. एल., त्रिची में सिविल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा खुली निविदा प्रणाली का बिल्कुल भी सहारा नहीं लिया गया था। मुझे खुली निविदा का एक भी उदाहरण याद नहीं है जैसा कि मैं भूल गया हूँ।

डी.

((iii) अपने कार्यकाल के दौरान मैंने एंटोमा हाइड्रो सिस्टम्स को अनुबंध के पुरस्कार को रद्द करने के लिए कुछ भी शुरू नहीं किया। यह सच है कि मैंने अनुबंध को रद्द करने के लिए कदम नहीं उठाए क्योंकि परिस्थितियाँ इसकी गारंटी नहीं देती थीं;

((iv) मैं बातचीत के लिए निविदाकारों को बुलाने के लिए सक्षम व्यक्ति हूँ और उस क्षमता में मैंने ठेकेदारों को कई पत्र लिखे;

ई.

((v) प्रदर्शनी पी-55 मेरे द्वारा एंटोमा हाइड्रो सिस्टम्स को लिखा गया 02.01.1993 का पत्र है जिसमें उनसे 07.01.1993 से पहले नया प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया है;

च

((vi) प्रदर्शनी पी-53 एक ऐसा पत्र है जो मेरे द्वारा मर्केटाइल कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन को लिखा गया है।

((vii) प्रदर्शनी पी-53 और पी-54 में इसका उल्लेख इस प्रकार किया गया है -

हमारी टेलीफोन पर बातचीत जारी है ";

जी.

(viii) प्रदर्शनी पी-39 के अनुसार, एक श्री आर. इलांगो ने 11.01.1993 पर आयोजित बैठक में मर्केटाइल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन का प्रतिनिधित्व किया। प्रदर्शनी पी-40 के अनुसार श्री जे. एन. जे. चंद्रन ने राघव इंजीनियरों और बिल्डर्स का प्रतिनिधित्व करते हुए 11.01.1993 पर आयोजित बैठक में भाग लिया। और

एच.

23 (1995) 3 एससीसी 351 ए

61

ए. श्रीनिवासुलु बनाम राज्य प्रतिनिधि. पुलिस निरीक्षक द्वारा [वी. रामसुब्रमणियन, जे.] ए.

(ix) सीमित निविदा नीति के अनुसार, निविदा जांच केवल योग्य और योग्य पक्षों को संबोधित की जानी चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए मैंने 25.11.1992 दिनांकित प्रदर्शनी पी-27 नोट तैयार किया है।

86. अपने मुख्य परीक्षण में, पीडब्लू-16 ने दावा किया कि कहीं न कहीं

1992 में उन्हें पहली बार ए-1 से विलवणीकरण संयंत्रों के निर्माण के प्रस्ताव के बारे में पता चला और एक दिन ए-1 ने उन्हें अपने कार्यालय में बुलाया और कहा कि उन्होंने चेन्नई में एक ऐसे व्यक्ति को पाया है जो एक गतिशील व्यक्ति, साधन संपन्न व्यक्ति, सहायक था।

और एक सफल व्यक्ति। मुख्य परीक्षण में यह उनका सकारात्मक दावा था कि उसी दिन ए-1 ने उन्हें निविदा दस्तावेज तैयार करने के लिए कहा और इसलिए वे अपने कार्यालय लौट आए और निविदा विभाग को निविदा दस्तावेज तैयार करने का निर्देश दिया। बाद में जो हुआ वह पीडब्लू-16 द्वारा मुख्य परीक्षा में इस प्रकार बताया गया है:

ग

“... कुछ समय बाद ए 1 ने मुझे फिर से अपने कार्यालय में बुलाया और मुझे बताया कि उन्होंने टी. डब्ल्यू. ए. डी. बोर्ड से कुछ ठेकेदारों के नाम और पते एकत्र किए हैं जो काम सौंपने की स्थिति में थे। फिर मैंने उनसे कहा कि निविदा दस्तावेज तैयार हैं और अगर ठेकेदारों के नाम और पते के साथ प्रस्तुत किया जाए तो मैं उन्हें भेज सकता हूँ। फिर, ए 1 ने निम्नलिखित 5 नामों को निर्धारित किया।

डी.

ई.

1) एंटोमो हाइड्रो सिस्टम्स, मद्रास। 2) ईस्ट कोस्ट बिल्डर्स, मद्रास।

3) की कंस्ट्रक्शन कंपनी, मद्रास को चालू करें। 4) राघव इंजीनियर्स एंड बिल्डर्स, मद्रास। 5) मर्केटाइल कंस्ट्रक्शन कंपनी, मद्रास।

च

मैंने इन नामों को नोट किया। फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे इन 5 कंपनियों में से किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, हो सकता है कि वे विशेष रूप से टीडब्ल्यूएडी बोर्ड के ठेकेदार हों और मुझे उनके बारे में पता न हो। इनमें से कुछ नाम जैसे ईस्ट कोस्ट बिल्डर्स, टर्न की कंस्ट्रक्शन कंपनी, राघव इंजीनियर्स और बिल्डर्स बड़ी कंपनियों के नामों के समान प्रतीत होते हैं, यानी कुछ बड़ी कंपनियों की सहायक कंपनियां हो सकती हैं। मैंने उन्हें आगे बताया कि एलएंडटी और जियो मिलर जैसी बड़ी कंपनियों को भी उस सूची में शामिल किया जा सकता है क्योंकि इससे सूची को कुछ सम्मान मिलेगा। ए 1 ने कुछ समय सोचा और मुझे बताया कि इन दोनों कंपनियों को भी शामिल किया जा सकता है।”

जी.

एच.

62

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

87. लेकिन जिरह में उन्होंने स्वीकार किया कि प्रदर्शनी पी-33 श्री कांताराव, प्रबंधक (सिविल/डिजाइन) द्वारा गणेशन (पीडब्लू-14) को लिखा गया एक पत्र था और उस पत्र में इस आशय का एक नोट था कि गणेशन ने इस मामले पर डीजीएम, सिविल के साथ चर्चा की है। पीडब्लू-16 ने आगे स्वीकार किया कि यह संभव था कि गणेशन ने उनके साथ चर्चा की होगी।

88. जिरह में उपरोक्त कथन से पता चलता है कि पीडब्लू-16 और पीडब्लू-14 के बीच चर्चा 22.10.1992 पर हुई थी। लेकिन ए-1 के साथ चर्चा और पांच नामों का निर्धारण पीडब्लू-16 के अनुसार भी नवंबर, 1992 में ही हुआ। वास्तव में, पीडब्लू-16 के अनुसार सीमित निविदा आमंत्रित करने से संबंधित पी-33 पत्र प्रदर्शित करें जो 22.10.1992 दिनांकित था।

ग

89. यदि अक्टूबर, 1992 में पीडब्लू-16 और किसी और के बीच चर्चा हुई थी और उस बैठक में सीमित निविदा के लिए जाने का निर्णय लिया गया था, तो यह समझ से परे है कि मूल पाप को ए-1 के लिए कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, विशेष रूप से जब पीडब्लू-16 और ए-1 के बीच चर्चा नवंबर, 1992 में हुई थी, जिसमें कथित रूप से चार फर्जी नामों और संभावित ठेकेदार के नामों का निर्धारण किया गया था।

डी.

90. पीडब्लू-16 ने जिरह के दौरान स्वीकार किया कि उसने ए-1 के साथ उस दिन चर्चा की जब निविदा दस्तावेज 'स्पीड पोस्ट' के माध्यम से भेजे गए थे और वह 26.11.1992 पर था। लेकिन डी. डब्ल्यू.-2 और डी. डब्ल्यू.-3 के साक्ष्य के माध्यम से यह रिकॉर्ड में लाया गया कि ए-1 अपनी सास की मृत्यु के कारण 26.11.1992 पर अनुपस्थित था। किसी भी मामले में, पीडब्लू-16 ने जिरह में स्वीकार किया कि उसने 25.11.1992 पर भी प्रदर्शनी पी-27 नोट पर हस्ताक्षर किए थे, जो उस तारीख से एक दिन पहले था जिस दिन उसने ए-1 के साथ चर्चा की थी।

ई.

91. पीडब्लू-16 द्वारा दी गई कहानी कि अन्य चार फर्म वास्तव में फर्जी फर्म थीं, उनके अपने बयान से इस आशय से गलत साबित होती है कि प्रदर्शनी पी-39 और पी-40 के अनुसार, दो व्यक्तियों ने उन चार फर्मों में से दो का प्रतिनिधित्व किया। यदि वे फर्म फर्जी थीं, तो इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि बैठक में उनका प्रतिनिधित्व कैसे किया गया था।

च

जी.

92. पीडब्लू-16 द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि प्रदर्शनी पी-53 और पी-54 (उन कंपनियों में से दो को लिखे गए पत्र) में एक संकेत था जैसे कि पत्र उनकी टेलीफोन पर हुई बातचीत की निरंतरता में थे। 93. दूसरे शब्दों में, पीडब्लू-16 द्वारा फर्जी फर्मों के रूप में ब्रांडेड चार फर्मों में से दो ने पीडब्लू-16 के साथ चर्चा की है और वे बैठकों में भी शामिल हुए हैं।

एच.

63

ए. श्रीनिवासुलु बनाम राज्य प्रतिनिधि. पुलिस निरीक्षक द्वारा [वी. रामसुब्रमणियन, जे.] ए.

क.

94. इन सब को सीमित करने के लिए, पीडब्लू-16 ने स्वीकार किया:

“ मैंने एंटोमा को अनुबंध देने की सिफारिश की जो सबसे कम निविदा देने वाला था। मैंने ए 5 को अनुबंध देने की सिफारिश की, ए 1 के ब्याज के कारण नहीं।”

95. इसलिए, यह दिखाने के लिए और कुछ नहीं चाहिए था कि पीडब्लू-16 श्रेय के योग्य नहीं था और एक स्टार गवाह के रूप में ऐसे व्यक्ति के आधार पर दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है।

96. यह पूछे जाने पर कि क्या बी. एच. ई. एल. को गलत तरीके से नुकसान हुआ है या क्या ए-5 या किसी अन्य फर्म, जिसके साथ वह जुड़े थे, को गलत तरीके से लाभ हुआ है, पी. डब्ल्यू.-24, जो बी. एच. ई. एल. के उप प्रबंधक (वित्त) थे, का सबूत महत्वपूर्ण है। अपनी प्रतिपरीक्षा में, पीडब्लू-24 ने इस प्रकार कहा:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

“...सी. बी. आई. अधिकारी द्वारा जाँच के दौरान उन्होंने मुझे एक विस्तृत लेखा प्रतियाँ भेजने के लिए कहा। उनके अनुरोध पर मैंने उन्हें भेजा। Ex. डी 1 उन खातों की वास्तविक प्रति है जो मैंने सी. बी. आई. को भेजे थे। जहां तक इस अनुबंध का संबंध है क्योंकि बैंक गारंटी को रद्द कर दिया गया था मेसर्स भेल त्रिची ने इस अनुबंध में कोई पैसा नहीं गंवाया है। वास्तव में ए. 5 ठेकेदारों का पैसा मेसर्स भेल त्रिची के साथ रु. 1,61,86,234/- तक है। इस राशि के अलावा बी. एच. ई. एल. द्वारा अभियुक्त संख्या 5 को उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए <आई. डी. 1,52,286/- की राशि देय है।

डी.

ई.

97. पीडब्लू-24 द्वारा की गई उपरोक्त स्वीकारोक्ति से दो बातें सामने आती हैं। पहला यह है कि जाँच के समय भी, पीडब्लू-24 ने आई. ओ. को एक विस्तृत लेखा प्रति प्रदान की थी, जिसमें दिखाया गया था कि बी. एच. ई. एल. को कोई नुकसान नहीं हुआ था और इसके विपरीत, रु. एंटोमा को 2 करोड़ 60 लाख रुपये का भुगतान किया जाना था। लेकिन कुछ अस्पष्ट कारणों से, उक्त खातों के बयान की प्रति सी. बी. आई. द्वारा अदालत के समक्ष पेश नहीं की गई। पीडब्लू-24 की प्रतिपरीक्षा करते समय इसे रक्षा प्रदर्शनी डी-1 के रूप में चिह्नित किया जाना था। इसलिए, यह स्पष्ट है कि खाते के इस विवरण को दबा दिया गया था, ताकि एक तस्वीर को इस तरह चित्रित किया जाए जैसे कि बी. एच. ई. एल. को गलत नुकसान हुआ हो।

च

जी.

98. ऊपर निकाली गई पीडब्लू-24 की प्रतिपरीक्षा से जो दूसरी बात निकलती है, वह यह है कि बैंक गारंटी को लागू करने और पहले से भुगतान किए गए धन के लिए उसी को विनियोजित करने के बाद भी, बी. एच. ई. एल. के पास ठेकेदार का रु. 1,61,86,234/- बचा था, इसके अलावा बी. एच. ई. एल. द्वारा ए-5 को किए गए काम के लिए देय राशि Rs.98,52,286/- थी।

एच.

64

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

99. इसलिए, यह स्पष्ट है कि यह ए-5 ही था जो वास्तव में अनुबंध हासिल करके आर्थिक और कानूनी रूप से गड़बड़ में पड़ गया था। किसी भी लाभ को बहुत कम गैरकानूनी लाभ बनाने के बजाय, ठेकेदार ने बैंक गारंटी लागू करने के अलावा उपरोक्त दो राशियों को खो दिया है। 100. दुर्भाग्य से, ट्रायल कोर्ट इस बयान के कारण एक जाल में फंस गया कि एंटोमा हाइड्रो सिस्टम्स द्वारा जुटाने की अग्रिम राशि से 1,000/- रुपये की राशि एक अन्य फर्म के खाते में स्थानांतरित की गई थी, जिसमें ए-5 से ए-7 भागीदार थे। ट्रायल कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि साझेदारी फर्म मेसर्स इंसेक्टिसाइड्स एंड एलाइड केमिकल्स को इस राशि तक गलत लाभ हुआ था, एक पल के लिए यह भूलते हुए कि यदि यह बी. एच. ई. एल. का पैसा था जो उक्त फर्म को प्राप्त हुआ था, तो उसी तर्क से जो भुगतान किया गया था, वह फर्म का पैसा होना चाहिए था। दो अलग-अलग मानदंड नहीं हो सकते हैं, एक साझेदारी फर्म द्वारा प्राप्त धन से संबंधित है और दूसरा बीएचईएल द्वारा प्राप्त धन से संबंधित है। वास्तव में, जुटाने के लिए अग्रिम राशि का उपयोग सामग्री की खरीद के लिए किया जाता है। बी. एच. ई. एल. के डी. जी. एम. (ई. एम. एस.) ने जांच की कि पीडब्लू-34 ने मुख्य जांच में भी कहा कि प्रारंभिक चरणों में अनुबंध बहुत अच्छा रहा था और पानी की गुणवत्ता परीक्षण के चरण तक, ठेकेदार अच्छा कर रहा था। इसलिए, जुटाने के लिए अग्रिम राशि खर्च करना आवश्यक था। केवल उस व्यक्ति के आधार पर संदेह नहीं किया जा सकता है जिसे भुगतान किया गया था। यदि बी. एच. ई. एल. द्वारा ए-5 को जो भुगतान किया गया था, वह ए-6 और ए-7 द्वारा साझा किया गया था, तो बैंक गारंटी के आह्वान के माध्यम से ए-5 से जो प्राप्त हुआ, उसका लाभ यह तर्क देने के लिए नहीं लिया जा सकता है कि ए-6 और ए-7 ने धन का भुगतान नहीं किया। इस संबंध में निचली अदालत द्वारा अपनाया गया तर्क पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण था। 101. ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने पीडब्लू-2 (एक चार्टर्ड एकाउंटेंट), पीडब्लू-3 (चेन्नई टेलीफोन के एक अधिकारी) और कुछ अन्य लोगों के मौखिक साक्ष्य को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए माना कि प्रदर्शनी पी-26 चिट में शामिल चार अन्य फर्मों के नाम फर्जी थे। लेकिन निचली अदालत और उच्च न्यायालय दोनों ने पीडब्लू-16 द्वारा की गई इस स्वीकारोक्ति की अनदेखी की कि उन्होंने उन चार फर्मों में से कम से कम दो के साथ बातचीत की और उन दोनों फर्मों के प्रतिनिधियों ने बैठकों में भाग भी लिया।

ग

डी.

ई.

च

जी.

102. निचली अदालत और उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दो बड़ी कंपनियों के नाम केवल अपनाई गई प्रक्रिया को विश्वसनीयता देने के लिए प्रदर्शनी पी-26 चिट में शामिल किए गए थे। लेकिन एल एंड टी कंपनी के प्रबंधक पीडब्लू-4 के बयान के माध्यम से यह रिकॉर्ड में था कि उन्हें भेल से एक निविदा जांच प्राप्त हुई थी। यदि नामों का समावेश ए

एच.

65

ए. श्रीनिवासुलु बनाम राज्य प्रतिनिधि. पुलिस निरीक्षक द्वारा [वी. रामसुब्रमणियन, जे.] ए.

उन दो कंपनियों में से ए-1 ने पत्र भेजने का जोखिम नहीं उठाया होगा और वह भी एक कंपनी को।

एल एंड टी जैसी कंपनी। इसलिए, हमारा विचार है, (i) पीडब्लू-16 का साक्ष्य श्रेय के योग्य नहीं था; (ii) यह मानते हुए भी कि इसकी कुछ विश्वसनीयता है, उनके बयान कि "उन्होंने ए-5 को अनुबंध देने की सिफारिश ए-1 के हित के कारण नहीं की", ने पूरी इमरत को ध्वस्त कर दिया, जिस पर अभियोजन पक्ष का मामला बनाया गया था; और (iii) कि ए-1 को इन अपराधों के करने से जोड़ने के लिए कोई अन्य सबूत नहीं था।

103. वास्तव में, दोनों न्यायालयों द्वारा धारा 120 बी के तहत अपराध का दोषी पाया जाने वाला एकमात्र व्यक्ति ए-1 था। इसलिए, एक तर्क दिया गया कि एक भी व्यक्ति को आपराधिक साजिश का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन इस तर्क को

अदालतों ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि पीडब्लू-16 दूसरा व्यक्ति था जिसके साथ ए-1 ने साजिश रची थी। दूसरे शब्दों में, निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया तर्क यह था कि केवल ए-1 और पीडब्लू-16 साजिश का हिस्सा थे। इस तरह का तर्क मूल आरोप से एक बड़ी चढ़ाई थी कि ए-1 से ए-7 ने बी. एच. ई. एल. को गलत नुकसान पहुंचाने और ए-5 से ए-7 को गलत लाभ देने के लिए एक आपराधिक साजिश में प्रवेश किया। एक बार जब ए-5 से ए-7 के खिलाफ धारा 120 बी का अपराध नहीं बनता है, तो अभियोजन की नींव ही अस्थिर हो जाती है। इसलिए, हमारा विचार है कि धारा 420, 468 के साथ पठित धारा 120 बी, धारा 468 के साथ पठित धारा 471 और आई. पी. सी. की धारा 193 और पी. सी. अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) के साथ पठित धारा 13 (2) के तहत अपराधों के लिए ए-1 की सजा कायम नहीं रखी जा सकती है।

ग

डी.

ई.

104. हम आश्चर्यचकित हैं कि ए-1 को धारा 193 के तहत अपराध का दोषी पाया गया। धारा 193 केवल न्यायिक कार्यवाही के किसी भी चरण में दिए गए झूठे साक्ष्य या न्यायिक कार्यवाही के किसी भी चरण में उपयोग किए जाने के उद्देश्य से झूठे साक्ष्य के निर्माण पर लागू होती है। ए-1 के खिलाफ आरोप आई. पी. सी. की धारा 193 के तहत किसी भी स्पष्टीकरण से दूर से जुड़ा नहीं था। इसलिए, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त अपराधों के लिए ए-1 को दोषी ठहराने और उसे अलग-अलग शर्तों के कारावास और अलग-अलग राशियों के जुर्माने की सजा देने के निर्णय को उलट दिया जा सकता है।

च

जी.

ए-4 के बारे में

105. जैसा कि निचली अदालत के फैसले से देखा जा सकता है, ए-4 को आई. पी. सी. की धारा 109 के साथ धारा 420, 468, आई. पी. सी. की धारा 471 के साथ धारा 468 और आई. पी. सी. की धारा 193 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था।

एच.

66

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

106. जैसा कि हमने ए-1 के मामले से संबंधित अंतिम पैराग्राफ में बताया है, आई. पी. सी. की धारा 193 न्यायिक कार्यवाही के किसी भी चरण में जानबूझकर दिए गए झूठे साक्ष्य के लिए सजा से संबंधित है। इसमें न्यायिक कार्यवाही के किसी भी चरण में उपयोग किए जाने के उद्देश्य से झूठे साक्ष्य का निर्माण भी शामिल है। धारा 193 के तहत तीन स्पष्टीकरण हैं। धारा 193 के तहत स्पष्टीकरण 2 किसी न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के लिए कानून द्वारा प्रारंभिक रूप से निर्देशित जांच को न्यायिक कार्यवाही का एक चरण बनाता है, हालांकि वह जांच न्यायालय के समक्ष नहीं हो सकती है। इसी तरह, स्पष्टीकरण 3 किसी न्यायालय द्वारा विधि के अनुसार निर्देशित और न्यायालय के अधिकार के तहत संचालित जांच को न्यायिक कार्यवाही का एक चरण बनाता है, हालांकि वह जांच न्यायालय के समक्ष नहीं हो सकती है।

ग

107. दिलचस्प बात यह है कि ऐसा कोई आरोप नहीं था कि ए-1 या ए-3 या ए-4 ने या तो झूठा सबूत दिया या न्यायिक कार्यवाही के किसी भी चरण में झूठा सबूत गढ़ा, जो धारा 193 के तहत तीन स्पष्टीकरणों में से किसी के भीतर आता है। लेकिन दुर्भाग्य से, निचली अदालत ने ए-4 को धारा 193 के तहत अपराध का दोषी पाया, आरोप पत्र में कोई विशिष्ट आरोप लगाए

बिना और गुण-दोष पर कोई विशिष्ट निष्कर्ष निकाले बिना। 108. जैसा कि ए-4 के विद्वान वकील श्री एस. आर. रघुनाथन ने ठीक ही तर्क दिया है, कोई भी न्यायालय आई. पी. सी. की धारा 193 के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, सिवाय उस न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय के लिखित शिकायत के जिसके अधीन वह न्यायालय है। यह बार संहिता की धारा 195 (1) (बी) (आई) में पाया जाता है। किसी भी अदालत या किसी भी अदालत द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा कभी भी कोई शिकायत नहीं की गई थी कि ए-1 या ए-3 या ए-4 ने आई. पी. सी. की धारा 193 के तहत दंडनीय अपराध किया है। लेकिन दुर्भाग्य से, निचली अदालत ने ए-1, ए-3 और ए-4 को बिना किसी समझदारी के धारा 193 के तहत अपराध का दोषी ठहराया और इसे उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है।

डी.

ई.

च

109. यहां तक कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, ए-4 द्वारा निभाई गई एकमात्र भूमिका 23.12.1992 पर गठित समिति का सदस्य होना था। समिति की प्रकृति और यह कि क्या यह एक निविदा समिति या वार्ता समिति थी, के बारे में बहुत कुछ करने की मांग की गई थी। समिति की भूमिका और नाम के बारे में उत्पन्न गर्मी और धूल के कारण, इस बात की पूरी तरह से अनदेखी की गई कि यह समिति पुल के नीचे बहुत पानी बह जाने के बाद ही सामने आई, (i) एक प्रतिबंधित निविदा के लिए जाने का निर्णय लेकर; (ii) सात चिन्हित ठेकेदारों को निविदा नोटिस जारी करके; (iii) पांच ठेकेदारों से प्रस्ताव प्राप्त करके; और (iv) 18.12.1992 A पर निविदा दस्तावेज खोलकर।

जी.

एच.

67

ए. श्रीनिवासुलु बनाम राज्य प्रतिनिधि. पुलिस निरीक्षक द्वारा [वी. रामसुब्रमणियन, जे.] ए.

आगे की प्रक्रिया के उद्देश्य से। धोखाधड़ी के अपराध को स्थापित करने के उद्देश्य से, जो महत्वपूर्ण है वह शुरुआत में मानसिकता है, जब आपराधिक साजिश रची गई थी। जिस समय अक्टूबर/नवंबर, 1992 में कथित रूप से आपराधिक साजिश रची गई थी, उस समय ए-3 और ए-4 तस्वीर में बिल्कुल भी नहीं थे। वे तस्वीर में केवल 23.12.1992 पर आए। वार्ता समिति के गठन के लिए दिनांकित 23.12.1992 नोट इस तथ्य को दर्ज करता है कि पाँच नामित ठेकेदारों ने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। सभी पाँच ठेकेदारों के नाम और पते, उनके द्वारा उद्धृत राशि और प्रस्तावों की प्राप्ति की तारीख और तरीका सभी दिनांकित 23.12.1992 नोट में एक तालिका के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इन सभी विवरणों पर ध्यान देने के बाद, 23.12.1992 की टिप्पणी तिथि समिति के गठन के पीछे के उद्देश्य को इस प्रकार बताती है:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

“चूंकि निविदाकारों द्वारा उद्धृत मूल्य बहुत अधिक है, इसलिए सीरियल Nos.1 से 3 के तहत सबसे कम तीन निविदाकारों के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव है।”

डी.

110. इसलिए, निचली अदालत और उच्च न्यायालय को इस तरह पढ़ना कि यह समिति, जिसमें ए-3, ए-4 और अनुमोदनकर्ता एक हिस्सा थे, वास्तव में एक निविदा समिति थी जिसकी एक बड़ी भूमिका थी, पूरी तरह से गलत धारणा है।

111. वास्तव में, अभियोजन पक्ष को पी. डब्ल्यू.-16 नामक अनुमोदनकर्ता की गवाही के बल पर खड़ा होना या गिरना पड़ा। लेकिन ए-3 और ए-4 द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में पीडब्ल्यू-16 ने यही कहा।

ई.

“ए 3 त्यागराजन और ए 4 चंद्रशेखरन का इस मामले में ठेकेदारों को चुनने से कोई लेना-देना नहीं था।उनका एकमात्र काम सबसे कम बोली लगाने वाले तीन लोगों के साथ बातचीत करना था।इसके साथ ही उनका काम खत्म हो जाएगा।ए 3 और ए 4 समिति के सदस्यों ने अपना काम अच्छी तरह से किया।इस मामले में ठेकेदार ने 50 प्रतिशत जुटाने के लिए अग्रिम दिया और समिति द्वारा बातचीत के कारण इसे घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया।वार्ता समिति ने राशि के लिए बैंक गारंटी पर जोर दिया था और बैंक गारंटी भी प्राप्त की थी।हालाँकि बातचीत जनवरी में ही पूरी हो गई थी, लेकिन 1993 का आशय पत्र केवल जुलाई 1994 में यानी 18 महीनों के बाद जारी किया गया था।यह सच है कि वार्ता समिति के प्रयासों के कारण कार्य आदेश जारी करने में 18 महीने की देरी के कारण ठेकेदार को दर में वृद्धि नहीं करने के लिए राजी किया गया था।”

च

जी.

एच.

68

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

112. पीडब्लू-16 द्वारा ए-3 और ए-4 को क्लिन चिट देने के उपरोक्त दावे के बावजूद, निचली अदालत ने दोनों को इस जटिल तर्क पर दोषी पाया कि वे एक निविदा समिति का हिस्सा थे और

“ प्रदर्शनी पी-36 (निविदा समिति की कार्यवाही) में प्रत्येक शब्द और प्रत्येक विवरण उनके द्वारा बी. एच. ई. एल. को धोखा देने के उद्देश्य से लिखा गया था और “यदि ए-3 और ए-4 निर्दोष थे तो उन्हें पूछताछ करनी चाहिए थी और ठेकेदारों के बारे में विवरण पूछना चाहिए था।” इस तरह का तर्क

विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया और विचारण न्यायालय द्वारा अनुमोदित और उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित पूरी तरह से विकृत था।

113. जैसा कि विद्वान वकील ने सही तर्क दिया, ए-4 की निविदाकारों को चुनने में कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन निविदाकारों से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद ही तस्वीर में प्रवेश किया।मान लीजिए, ए-4 पीडब्लू-16 और ए-3 दोनों के अधीन था।

ग

114. पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह इंगित किया जाना चाहिए कि सक्षम प्राधिकारी ने पीसी अधिनियम के तहत अपराधों के लिए ए-3 और ए-4 पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने ए-4 को सह-साजिशकर्ता नहीं पाया, यही कारण है कि उसे आई. पी. सी. की धारा 120-बी के तहत अपराध का दोषी नहीं ठहराया गया। आई. पी. सी. की धारा 193 को पूरी तरह से संदर्भ से बाहर शामिल किया गया था।

डी.

115. उपरोक्त सभी कारणों से, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए विचारण न्यायालय द्वारा ए-4 की दोषसिद्धि पूरी तरह से अस्थिर है और इसे दरकिनार किया जा सकता है।

ई.

ए-7 के बारे में

116. ए-7 की भूमिका यह थी कि उन्होंने चार अलग-अलग फर्जी फर्मों के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट के लिए आवेदन किया और प्राप्त किया, जिसमें से प्रत्येक के लिए बी. एच. ई. एल. के पक्ष में आई. डी. 1,000/- की राशि मांगी गई ताकि यह प्रतीत हो सके कि वे वास्तविक फर्म हैं, हालांकि वे अस्तित्व में नहीं थीं। ए-7 पर बी. एच. ई. एल. को ए-5 और ए-6 के साथ गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया था। 4. 42 करोड़। ए-7 पर ए-1 और ए-2 को अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके और अपने लिए आर्थिक लाभ प्राप्त करके आपराधिक कदाचार करने के लिए उकसाने का भी आरोप लगाया गया था।

च

जी.

117. यह स्थापित करने के लिए कि ए-7 ने चार फर्जी फर्मों के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट जारी करने के लिए विभिन्न बैंकों में आवेदन दायर किए थे, अभियोजन पक्ष ने पी. डब्ल्यू.-22, इंडियन बैंक के एक वरिष्ठ प्रबंधक, पी. डब्ल्यू.-32, भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक, पी. डब्ल्यू.-40, बैंक ऑफ मद्रास के वरिष्ठ प्रबंधक, पी. डब्ल्यू.-41, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के मुख्य प्रबंधक और पी. डब्ल्यू.-30, हस्तलेखन विशेषज्ञ से पूछताछ की। अभियोजन पक्ष ने ए को चिह्नित किया

एच.

69

ए. श्रीनिवासुलु बनाम राज्य प्रतिनिधि. पुलिस निरीक्षक द्वारा [वी. रामसुब्रमणियन, जे.] ए.

पी-66, पी-76, पी-90 और पी-92, जो चार फर्जी फर्मों के नाम पर जमा किए गए आवेदन थे, इन बैंकों को डिमांड ड्राफ्ट जारी करने के लिए प्रदर्शित करते हैं।

118. पीडब्लू-22, जिसके माध्यम से प्रदर्शनी पी-66 को चिह्नित किया गया था, ने मुख्य परीक्षा में भी यह नहीं कहा कि आवेदन पत्र पर ए-7 द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। पीडब्लू-32, जिनके माध्यम से प्रदर्शनी पी-76 को चिह्नित किया गया था, ने मुख्य परीक्षा में कहा कि डिमांड ड्राफ्ट जारी करने के लिए आवेदन की तारीख को वह उस शाखा में काम नहीं कर रहे थे और वह छह साल बाद शाखा में शामिल हुए। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से मांग मसौदा आवेदन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन उन्होंने मुख्य परीक्षा में दावा किया कि ए-5 और ए-7 के पिता ए-6 उस परिसर के मालिक थे जिसमें शाखा स्थित थी और वह प्रदर्शनी पी-76 में ए-7 के हस्ताक्षर की पहचान कर सकते थे। हालांकि, जिरह में उन्होंने स्वीकार किया:

ग

“आवेदक के हस्ताक्षर शाखा में उपलब्ध थे। मैंने डीडी आवेदन में हस्ताक्षर के साथ नमूना हस्ताक्षर की तुलना नहीं की। जब सी. बी. आई. ने मुझसे पूछताछ की, तो मैंने आवेदक के नमूना हस्ताक्षर के लिए नहीं कहा।”

डी.

119. पीडब्लू-40, जिनके माध्यम से प्रदर्शनी पी-90 को चिह्नित किया गया था, ने मुख्य परीक्षा में कुछ नहीं कहा कि ए-7 ने डिमांड ड्राफ्ट के लिए आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने केवल मांग मसौदा आवेदन पत्र और उस पार्टी की पहचान की जिसकी ओर से मांग मसौदा लिया गया था। दूसरे शब्दों में, पीडब्लू-40 ने पीडब्लू-22 की तरह ए-7 को उस व्यक्ति के रूप में शामिल नहीं किया जिसने कुछ फर्जी फर्मों की ओर से डिमांड ड्राफ्ट जारी करने के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर किए थे।

ई.

च

120. पीडब्लू-41 जिनके माध्यम से प्रदर्शनी पी-92 को चिह्नित किया गया था, केवल यह बताया गया था कि मांग मसौदा किसने प्राप्त किया था। उन्होंने विशेष रूप से ए-7 का नाम आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले या डिमांड ड्राफ्ट प्राप्त करने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं लिया।

121. वास्तव में, पीडब्लू-40 ने कहा कि आई. ओ. द्वारा संहिता की धारा 161 के तहत कोई बयान दर्ज नहीं किया गया था, हालांकि उनकी जांच की गई थी। इसी तरह, पीडब्लू-41 ने कहा कि इंस्पेक्टर, सीबीआई द्वारा उनसे पूछताछ की गई थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि धारा 161 के तहत बयान दर्ज किया गया था या नहीं।

जी.

122. इस प्रकार, अभियोजन पक्ष द्वारा जांच किए गए चार में से तीन बैंक अधिकारियों ने यह दिखाने के लिए कि ए-7 ने चार फर्जी फर्मों की ओर से डिमांड ड्राफ्ट के लिए आवेदन किया था, ए-7 की पहचान उस व्यक्ति के रूप में नहीं की जिसने आवेदन किया था।

एच.

70

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

ड्राफ्ट की मांग करें। उन्होंने प्रदर्शनी पी-66, पी-90 और पी-92 में ए-7 की लिखावट की भी पहचान नहीं की। अभियोजन पक्ष के पक्ष में कुछ कहने वाला एकमात्र व्यक्ति पीडब्लू-32 था और यह प्रदर्शनी पी-76 के संबंध में था।

123. यह उनके साक्ष्य की फिसलन प्रकृति के कारण है कि अभियोजन पक्ष ने हस्तलेखन विशेषज्ञ द्वारा जांच के लिए प्रदर्शनी पी-66, पी-76, पी-90 और पी-92 भेजने का फैसला किया। हस्ताक्षर विशेषज्ञ की जांच पीडब्लू-30 के रूप में की गई थी और उनकी रिपोर्ट दिनांक 16.09.1998 को प्रदर्शनी पी-68 के रूप में चिह्नित किया गया था।

124. ए-5 के नमूना लेखन और हस्ताक्षर की पहचान पीडब्लू-30 द्वारा एस 1 से एस 31 के रूप में की गई थी और प्रदर्शनी पी-70 के रूप में चिह्नित किया गया था। ए-7 के नमूना लेखन/हस्ताक्षर की पहचान एस 63 से एस 73 ए के रूप में की गई थी और प्रदर्शनी पी-75 श्रृंखला के रूप में चिह्नित किया गया था।

ग

125. मुख्य परीक्षा में, पी. डब्ल्यू.-30, हस्तलेखन विशेषज्ञ ने कहा कि उनकी राय में, प्रदर्शनी पी-70 में एस 1 से एस 31 के रूप में चिह्नित नमूना लेखन/हस्ताक्षर के लेखक, कुछ दस्तावेजों में लाल घेरे वाले प्रश्न लेखन लिखने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति थे। प्रदर्शनी पी-70 में पहचाने गए नमूना लेखन और हस्ताक्षरों का लेखक ए-5 था न कि ए-7।

डी.

126. इसी तरह, पीडब्लू-30 ने एस 40 और एस 41 में प्रदर्शनी पी-73 के रूप में चिह्नित नमूना लेखन के लेखक की पहचान प्रदर्शनी पी-26 लिखने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में की। यह के. भास्कर राव (पीडब्लू-16) से संबंधित था और संदर्भ उस चिट के लिए था जिसमें मूल रूप से पाँच फर्मों के नाम निर्धारित किए गए थे और बाद में दो के नाम शामिल किए गए थे। इसी तरह, पीडब्लू-30 को मुख्य परीक्षा में पहचाना गया, प्रदर्शनी पी-74 में एस 42 से एस 62 और एस 93 से एस 96 में चिह्नित नमूना लेखन उस व्यक्ति के रूप में है जिसके लेखन प्रदर्शनी पी-26 में पाए जाते हैं। एस 42 से एस 62 और एस 93 से एस 96 A-6 के थे। 127. इस प्रकार ए-5, पीडब्लू-16 और ए-6 के नमूना लेखन और हस्ताक्षरों को कुछ प्रश्नगत लेखन से संबंधित करने के बाद, हस्तलेखन विशेषज्ञ ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह स्पष्ट कर दिया कि उनके लिए हाथ में मौजूद सामग्री के आधार पर शेष प्रश्नगत वस्तुओं पर कोई राय व्यक्त करना संभव नहीं था। दूसरे शब्दों में, जहां तक ए-7 का संबंध है, पी. डब्ल्यू.-30 के रूप में जांच किए गए हस्तलेखन विशेषज्ञ ने अपनी मुख्य परीक्षा में भी अभियोजन पक्ष का बचाव नहीं किया। प्रदर्शनी पी-68 के रूप में

चिह्नित उनकी रिपोर्ट में ए-7 को उस व्यक्ति के रूप में शामिल नहीं किया गया था जिसकी लिखावट और हस्ताक्षर, प्रदर्शनी पी-66, पी-76, पी-90 और पी-92 में लिखे और हस्ताक्षर किए गए थे।

ई.

च

जी.

एच.

71

ए. श्रीनिवासुलु बनाम राज्य प्रतिनिधि. पुलिस निरीक्षक द्वारा [वी. रामसुब्रमणियन, जे.] ए.

क.

128. इस प्रकार, अभियोजन पक्ष की ओर से यह स्थापित करने में भारी विफलता थी कि प्रदर्शनी पी-66, पी-76, पी-90 और पी-92 ए-7 के हस्तलेखन/हस्ताक्षर में थे। यह अभियोजन पक्ष द्वारा पी. डब्ल्यू.-22, पी. डब्ल्यू.-32, पी. डब्ल्यू.-40 और पी. डब्ल्यू.-41 के रूप में बैंक अधिकारियों और पी. डब्ल्यू.-30 के रूप में लिखावट विशेषज्ञ की जांच के बावजूद है।

129. दुर्भाग्य से, ट्रायल कोर्ट ने पैराग्राफ 91 (एकमात्र पैराग्राफ जिसमें इस संबंध में कारण दिए गए थे) में एक बहुत ही जिज्ञासु तर्क अपनाया कि चूंकि वह कीटनाशकों और संबद्ध रसायनों के खाते में भेजे गए धन का लाभार्थी था, इसलिए उसे भागीदारी और जानकारी होनी चाहिए कि डिमांड ड्राफ्ट बी. एच. ई. एल. को धोखा देने के लिए खरीदे गए थे। इस तरह का तर्क इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से अस्वीकार्य है कि ए-7 पर जालसाजी का आरोप लगाया गया था और आई. पी. सी. की धारा 468 के तहत मांग मसौदे के लिए इन्हीं आवेदनों के संबंध में आरोप लगाया गया था। इसलिए, अभियोजन पक्ष के लिए जालसाजी साबित करना और यह भी दिखाना आवश्यक था कि इस तरह की जालसाजी का उद्देश्य धोखाधड़ी था। दोनों अनुपस्थित थे।

ग

डी.

130. सौभाग्य से उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के तर्क में कमी को महसूस किया। लेकिन ए-7 को किसी तरह दोषी ठहराने की अत्यधिक चिंता में, उच्च न्यायालय ने एक बहुत ही विचित्र मार्ग अपनाया, जिसका नाम है साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 के तहत विवादित हस्ताक्षरों के साथ स्वीकृत हस्ताक्षरों/लिखावटों की तुलना करने का कार्य करना।

131. धारा 73 को लागू करने के लिए, पहले कुछ हस्ताक्षर या लेखन होना चाहिए जिसे न्यायालय की संतुष्टि के लिए स्वीकार किया गया हो या साबित किया गया हो, जो उस व्यक्ति द्वारा लिखा या किया गया हो। यह धारा न्यायालय को यह भी अधिकार देती है कि वह न्यायालय में उपस्थित किसी भी व्यक्ति को शब्दों या आंकड़ों की तुलना करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से कोई भी शब्द या आंकड़े लिखने का निर्देश दे।

ई.

च

132. उच्च न्यायालय के समक्ष कोई हस्ताक्षर या लेखन उपलब्ध नहीं था, जिसे न्यायालय की संतुष्टि के लिए स्वीकार या साबित किया गया था। उच्च न्यायालय ने ए-7 को तुलना को सक्षम करने के उद्देश्य से कोई शब्द या आंकड़े लिखने का भी निर्देश नहीं दिया। धारा 73 में इस प्रकार निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना, उच्च न्यायालय ने एक नई प्रक्रिया का आविष्कार किया, ताकि गलत तर्क के माध्यम से निचली अदालत द्वारा दी गई दोषसिद्धि को बरकरार रखा जा सके।

जी.

133. वास्तव में, उच्च न्यायालय ने प्रदर्शनी पी-75 को ए-7 के स्वीकृत हस्ताक्षर और हस्ताक्षर वाला दस्तावेज माना और उसमें जो पाया गया उसकी तुलना प्रदर्शनी पी-66, पी-76, पी-90 और पी-92 में पाए गए हस्ताक्षरों से की।

एच.

72

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

134. लेकिन प्रदर्शनी पी-75 में जो कुछ भी था, उसे ए-7 ने कभी भी अपनी लिखावट में स्वीकार नहीं किया। प्रदर्शनी पी-75 को हस्ताक्षर विशेषज्ञ पीडब्लू-30 के माध्यम से चिह्नित किया गया था, और आई. ओ. द्वारा भी नहीं। कम से कम अगर आई. ओ. ने ए-7 के नमूना लेखन और हस्ताक्षर को प्रदर्शनी पी-75 के रूप में पहचाना और चिह्नित किया था, तो अभियोजन पक्ष के लिए यह तर्क देना संभव था कि नमूना हस्ताक्षर साबित हुए थे। लेकिन आई. ओ. ने प्रदर्शनी पी-75 की पहचान नहीं की। पीडब्लू-30, जिनके माध्यम से प्रदर्शनी पी-75 को चिह्नित किया गया था, ने सीधे ए-7 के नमूना लेखन प्राप्त नहीं किए। पीडब्लू-30 का यह कथन कि ए-7 के नमूना लेखन प्रदर्शनी पी-75 में हैं, केवल सुनी-सुनाई गवाही थी, क्योंकि उन्होंने सीधे उन नमूने के हस्ताक्षर प्राप्त नहीं किए थे। इस प्रकार, प्रदर्शनी पी-75 कभी साबित नहीं हुआ।

ग

135. यहां तक कि संहिता की धारा 313 के तहत पूछताछ में भी ए-7 से कोई विशिष्ट प्रश्न नहीं पूछा गया था कि क्या प्रदर्शनी पी-66, पी-76, पी-90, पी-92 और पी-75 उनकी लिखावट में थे और क्या उनमें उनके हस्ताक्षर थे। इसलिए, प्रदर्शनी पी-75 में जो शामिल था, उस पर हस्ताक्षर भी स्वीकार नहीं किए गए थे।

डी.

136. स्वीकार किए गए हस्ताक्षरों की स्वीकृति या प्रमाण के अभाव में, उच्च न्यायालय साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 का सहारा नहीं ले सकता था।

137. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष जैसे कि ए-7 ने फर्जी फर्मों के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट जारी करने के लिए आवेदन करके जालसाजी और धोखाधड़ी की है, पूरी तरह से अस्थिर है।

ई.

138. ए-7 के खिलाफ इंगित एकमात्र जुड़ाव लिंक उस फर्म के खाते में रु. 1,52,50,000/- की कुल सीमा तक धन का हस्तांतरण था जिसमें वह एक भागीदार था। यह अपने आप में कोई अपराध नहीं होगा। इसलिए, यह आरोप भी विफल होना चाहिए कि ए-7 ने अन्य अभियुक्तों को अपराध करने के लिए उकसाया। यह विशेष रूप से तब होता है जब ए-5, जिसकी स्वामित्व वाली संस्था ने अनुबंध प्राप्त किया था, ने न केवल अनुबंध खो दिया, बल्कि बी. एच. ई. एल. द्वारा बैंक गारंटी को लागू करने की भी अनुमति दी और इसके अलावा, रु। बी. एच. ई. एल. के पास अभी भी 2.6 करोड़ रुपये हैं। इसलिए ए-7 को दी गई दोषसिद्धि और सजा को कायम नहीं रखा जा सकता है।

च

जी.

निष्कर्ष

139. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, सभी अपीलों की अनुमति दी जाती है और सीबीआई मामलों के लिए विशेष अदालत के फैसले में ए को दोषी ठहराया जाता है।

एच.

ए. श्रीनिवासुलु बनाम राज्य प्रतिनिधि. पुलिस निरीक्षक द्वारा [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

विभिन्न अपराधों के लिए अपीलकर्ताओं और उनकी पुष्टि करने वाले उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है। अपीलार्थी सभी आरोपों से बरी हो जाते हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत जमानत बांड, यदि कोई हो, खारिज हो जाएंगे।

निधि जैन

अपीलों की अनुमति दी गई।

(सहायक: तमन्ना, एलसीआरए)

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.